प्रस्तावना

भारत चीन के युद्ध के समय चीन को समर्थन करने वाले, भारत द्वारा किये गये परमाणु परीक्षण का कड़ा विरोध करने वाले, शिक्षा के भारतीयकरण के विरूद्ध न्यायालय में याचिका लगाने वाले, जो अपनी पहचान प्रगतिशील, सिविल सोसाइटी या लिबरल के रूप में चाहते हैं। शासकीय प्रतिष्ठानों व उद्योगों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं तथा एन.जी.ओ., मानवाधिकार, साहित्यिक व कला मंच जिनके माध्यम है। एक दूसरे को मैगसेसे व उसके समकक्ष आदि पुरस्कार दिलाना जिनकी फितरत है। पत्रकारिता , पुस्तक, फिल्म, इनके आतंक फैलाने के हथियार हैं। असहिष्णुता, अभिव्यक्ति की आजादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे जिनके प्रिय जुमले हैं। प्राध्यापक, पत्रकार, अधिवक्ता व एक्टिविस्ट जिनका पेशा है और प्रधानमंत्री, भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नहीं बल्कि भारत को अपना शत्रु मानते हैं और भारत को टुकड़ों-टुकड़ों में देखना चाहते हैं। जनसुनवाई और आटीआई जिनके माध्यम हैं। गुरमेहर, कन्हैया, पंखुडी व शहैला जिनके नूतन संस्करण हैं। इनका शिकार होते हैं विवि में मानिविकी विषयों में अध्ययनरत ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थी। 2014 से इनकी तिलमिलाहट बढ़ी है। अवार्ड वापसी, असहिष्णुता, वेमूला से लेकर , जेएनयू, एएमयू होते हुए , हिन्दुओं में जातिय संघर्ष आदि षडयंन्त्रों तक जिम्मेदार है यह जमात। इनको वाममार्गी, माओवादी, कम्युनिस्ट कहा जाता है परन्तु एक ही शब्द का सम्बोधन देना हो तो वह है **अरबन नक्सलवादी।**

राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण विमर्श आकर शीघ्र चले जाते हैं समाज की स्मृति में संक्षिप्त समयावधि तक रहते हैं। समाज की सतत सजगता हेतु मुख्य धारा के हिन्दी समाचार पत्र-पत्रिकाओं में ''अरबन-नक्सल'' विषयों पर प्रकाशित आलेखों का संकलन है यह पुस्तिका।

अनुक्रमणिका

1. माओवाद का शहरी स्वरूप	- आशीष कुमार 'अंशु'	5
2. नक्सलवादियों के स्लीपिंग सेलों...	- अजय सेतिया	9
3. शहरी नक्सल पर भारी हमला	- विवेक अग्निहोत्री	12
4. शहरी नक्सल के खतरनाक मंसूबे	- अभिनव प्रकाश	16
5. भारत तेरे टुकडे होंगे...	- मनु त्रिपाठी	20
6. बौद्धिक आतंकवाद	- डा. नीलम महेंद्र	23
7. कौन हैं यह लोग	- हितेश शंकर	26
8. साजिश के सूत्रधार	- ज्योतिरादित्य	27
9. बड़ी हैसियत वाले नक्सली समर्थक	- अवधेश	30
10. शहरी नक्सली कानून से ऊपर नहीं	- शौर्य रंजन	33
11. घातक गठजोड़	- ज्ञानेन्द्र भरतिया	36
12. शहरी नक्सलवाद का असली चेहरा	- मकरन्द परांजपे	40
13. अरबन नक्सली अग्निवेश	- विनय	42
14. जेएनयू में पनपती पंखुडियां	- वर्षा सैनी	47
15. समाचार में नक्सली विचार	- अंजनी झा	49

माओवाद का शहरी स्वरूप

अगस्त 2008 में बिहार में भयानक बाढ़ आई थी। बताया गया था कि नेपाल का कुसहा बांध टूटने की वजह से यह बाढ़ आई । यही वह साल था, जब पहली बार मेरा परिचय 'अरबन नक्सल' यानि शहरी नक्सलवाद शब्द से हुआ था। बिहार में बाढ़ का पानी उतर चुका था। एक शाम 'बाढ़ मुक्ति अभियान' के संयोजक दिनेश कुमार मिश्र का फोन आया। टिकट भिजवा दिया है, पटना आना है। उनके आदेश के बाद पटना पहुंच गया। देश के एक दर्जन पत्रकारों के साथ बिहार की बाढ़ की त्रासदी को समझने के लिए पांच दिनों की यह एक यात्रा थी। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में कोलकाता से कॉमरेड संकर रॉय, दिल्ली से राकेश भट्ट और हिमांशु उपाध्याय, पुणे से अभिजीत घोडपड़े, मुम्बई से नितिन चन्द्रा जैसे कई फिल्मकार और पत्रकार शामिल हुए थे। इसी यात्रा में नेपाल की सीमा में प्रवेश करते ही एक व्यक्ति हमारी गाड़ी में आ चढ़ा। वह हमारे बीच नेपाल का प्रतिनिधि और पूरी यात्रा में मार्गदर्शक बना। यात्रा के दौरान उसने अपना परिचय स्वयं ही दिया कि वह माओवादी है। उन दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री माओवादी नेता पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड हुआ करते थे।

उससे बातचीत शुरू हुई तो लंबी चली। इस दौरान माओवाद और माओवादियों के कामकाज को समझने का अवसर भी मिला। माओवादी नेता ने बताया कि उनके यहां तीन स्तरीय व्यवस्था है। माओवादी सेना के लोग जंगल मे रहते हैं। वहां अभ्यास करते हैं और हमले की रणनीति बनाते हैं। उनके लिए धन लाना और तैयारी के संबंध में धन मुहैया कराने वालों तक जानकारी पहुंचाने का काम एक छोटा समूह करता है। जिसका जंगल और नगरीय क्षेत्रों के बीच जाना-आना लगा रहता है। वह जंगल की खबर शहर तक और शहर की खबर जंगल तक पहुंचाता है।

उसने यह बात बड़बोलेपन में ही कही थी कि- ''जब भी दिल्ली के लाल किले पर हमारा झंडा लहराएगा, उसके बाद तुम देखकर चौंक जाओगे कि

कौन-कौन और कैसे-कैसे लोग हमारे साथ हैं?''

उस माओवादी की बात अरबन नक्सलियों के नाम पर देश में हुई गिरफ्तारियों के बाद बार-बार याद आती है, ''चौंक जाओगे''। वास्तव में जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, वह चौंकाने वाले ही हैं। और सच कहूँ तो नहीं भी हैं। अपने आस-पास घट रही घटनाओं को लेकर जो चौकस हैं, वह बिल्कुल इन नामों को सुनकर नहीं चौंकेंगे क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, नक्सलियों से संबंध का उनका पुराना इतिहास रहा है।

मेरे ही सवाल के जवाब में एक और बात उस माओवादी नेता ने बताई थी, जिसका उल्लेख यहां महत्वपूर्ण जान पड़ता है। सवाल था। चीन आप लोगों को हथियार से मदद क्यों कर रहा है? क्या आप लोग चीन के उद्देश्य की पूर्ति भारत में कर रहे हैं? उस माओवादी ने स्वीकार किया कि वे चीन का हथियार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कहना था कि हथियार की खरीद वह सरकार से नहीं करता। उनके पास चीन का जो हथियार है, वह अवैध है और उस हथियार को वे पैसे देकर खरीदते हैं। मेरा अगला सवाल था - ''हथियार खरीदने के लिए इतना पैसा कहां से आता है?'' उसने मुस्कुराते हुए, संक्षिप्त सा जवाब दिया - **''दिल्ली से''।**

यह मेरा पहला परिचय माओवाद के महानगरीय रिश्ते से था। इसका मतलब स्पष्ट था कि कुछ ऐसे लोग दिल्ली में मौजूद थे जो राजधानी में बैठकर ना सिर्फ नेपाल के माओवादियों को धन मुहैया करा रहे थे, बल्कि वे नेपाल के जंगलों में चल रही माओवादी गतिविधियों में दखल भी रखते थे।

इस बात को अधिक बल मिला बस्तर, छत्तीसगढ़ के उस कांग्रेस के नेता से मिलकर जिसने नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की योजना बना ली थी। वह थे महेन्द्र कर्मा।

सलवा जुडूम सफल भी हो रहा था, लेकिन नक्सलियों के अरबन नेटवर्क की सक्रियता की वजह से ना सलवा जुडूम और ना ही महेन्द्र कर्मा अपना उद्देश्य हासिल कर पाए। सलवा जुडूम पर न्यायालय ने रोक लगा दी और महेन्द्र कर्मा को नक्सलियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। महेन्द्र कर्मा ने

| ₹ - समिधा |

अन्य पुस्तको की pdf के लिए
टेलीग्राम पर ₹-समिधा चैनल से जुड़े।

🙏

बताया था, ''यदि आंदोलन में इतनी खामियां थीं तो हम जो शीर्ष नेतृत्व में थे, एक भी शिकायत, एक भी एफआईआर मेरे खिलाफ क्यों नहीं आई? हत्या, बलात्कार, लूट का आरोप सलवा जूडूम पर लगता रहा, हम तो आन्दोलन की अगली पंक्ति में थे, मुझ पर यह आरोप क्यों नहीं लगे?''

नक्सलियों का अरबन नेटवर्क सलवा जुडूम के समय अति सक्रिय हो गया था। यदि मनमोहन सिंह सरकार उस समय अपनी मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय दे देती तो आज अरबन नेटवर्क को लेकर पूरे देश में यह विमर्श ना खड़ा हुआ होता। मेघा पाटकर, विनायक सेन, सोनी सोढी आदि नाम उस समय चर्चित हुए थे।

दिवंगत महेन्द्र कर्मा ने बताया था – ''नक्सलियों की ताकत बंदूक में नहीं है उनकी नेटवर्किंग में है। ये ज़माना नेटवर्किंग का है। जिस नेता की नेटवर्किंग जितनी अच्छी, वह उतना बड़ा नेता है। सफल नेता है। सलवा जुडूम के माध्यम से उनका नेटवर्क कमजोर हो रहा था। उनके नेटवर्क का आदमी उन्हें छोड़कर मुख्य धारा में आ रहा था। हम उनका नेटवर्क कमजोर करके ही उन्हें मार सकते थे। उस दौरान अरबन नक्सली पत्रकारों ने अपवादों को, मीडिया में इस तरह उठाया जैसे पूरे बस्तर में यही हो रहा है। और वे सफल हुए।''

नक्सलियों को लेकर जैसे ही सरकार कोई एक्शन लेती है, दिल्ली में एक बड़ा वर्ग है जो सक्रिय हो जाता है। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब से लेकर जन्तर मंतर पर चहल-पहल बढ़ जाती है। कई चेहरे तो ऐसे हैं, जो नक्सलियों के प्रति अपनी सहानुभूति को छुपाते तक नहीं। कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी व्यक्त कर देते हैं।

नक्सलियों से जुड़े समाचार को लेकर यह बात अरूंधति राय, राहुल पंडिता, से लेकर आलोक पुतुल तक मानेंगे कि बस्तर की खबर आम खबरों की तरह बस्तर से रायपुर तक का सफर तय नहीं करती। बस्तर की खबर पहले किसी अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय अखबार-चैनल, रेडियो की खबर बनती है। उसके बाद रायपुर में उसका फॉलोअप छपता है। फिर सबसे अंत में जगदलपुर संस्करण में वह खबर पढ़ने को मिलती है।

क्या यह संभव है – बिना उस तार के जो महानगर में बैठे नक्सली को जंगल में बैठे नक्सली से जोड़ता हो। बात सिर्फ तार की नहीं है, हिस्सेदारी की भी है। जिस पर विस्तार से बात करते हैं बस्तर के पूर्व आईजी एसआरपी कगूरी। बकौल कगूरी – ''बस्तर से नक्सली सालाना 1100 करोड़ रूपए की वसूली करते हैं। यह पैसा उन माओवादियों को नहीं मिलता जो हथियार लेकर जंगल में आंधी-पानी और मलेरिया से जूझ रहा है। यह पैसा पहुंचता है नक्सलियों के अरबन नेटवर्क के पास। ये एक छोटा सा वर्ग है जो गैर सरकारी संगठन व मानवाधिकार के नाम पर, अध्येता या शोधार्थी के नाम पर इस दावे के साथ बस्तर में मौजूद होता है कि हम वहां काम कर रहे हैं। इस शहरी नेटवर्क का काम वहां नक्सलियों के मामले पर न्यायालय में लड़ना। सुरक्षा बलों पर बलात्कार का मुकदमा करवाना भर है। स्थानीय लोगों के जीवन में उनकी मौजूदगी से कोई परिवर्तन आया हो, ऐसा प्रयास मैंने बस्तर के अपने पूरे कॅरियर में इनकी तरफ से नहीं देखा।''

कगूरी यह भी कहते हैं – ''अरबन नक्सली संख्या में बेहद कम हैं लेकिन शक्तिशाली हैं। वे अपने झूठ के दम पर पूरी दुनिया में बस्तर की एक छवि गढ़ने में कामयाब हुए हैं। इसलिए मैं बस्तर को इन अर्बन नक्सलियों की नजर से देखने की जगह बस्तर आकर देखने का ही सुझाव सभी को देता हूं।''

बहरहाल, नक्सली कहते हैं कि वे जनजाति के हक के लिए लड़ते हैं और बस्तर में जिन लोगों की हत्या नक्सलियों ने की, उनमें 99 फीसदी जनजाति ही थे। बस्तर के नक्सलियों के संबंध में यह जानना आवश्यक है कि वहां के नक्सली वास्तव में नक्सली नहीं हैं। वह पीड़ित हैं। उसका शोषण हैदराबाद और महाराष्ट्र के नक्सली कर रहे हैं। बस्तर के नक्सली जो जंगल में हथियार लेकर खड़े हैं वे मजदूरी करने के लिए और सीआरपीएफ की गोली खाने के लिए रखे गए हैं। उनको बस्तर की 1100 करोड़ की वसूली में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती क्योंकि उस पैसे का बड़ा हिस्सा नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के पास पहुंच जाता है।

साभार-पाञ्चजन्य – ***आशीष कुमार 'अंशु'***

नक्सलियों के स्लीपिंग सेलों पर कार्यवाही

भारत सरकार को जो कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, वह इसे आखिरी में उठा रही है । नक्सलियों के स्लीपिंग सेलों की भी धरपकड़ शुरू हो गई है । नक्सलियों के स्लीपिंग सेलों पर भी बहुत देर से कार्रवाई शुरू की गई है। देश भर में कई जगह छापे मारे गए । जिनमें जाने माने सफेदपोश नक्सली पकड़े गए हैं। इन में प्रमुख हैं वरवर राव, सुधीर धावले, सुधा भारद्वाज , सुरेन्द्र गद्लिंग , महेश राउत , रोना विल्सन । सब से ज्यादा चर्चित स्वामी अग्निवेश पता नहीं अभी तक क्यों नहीं धरा गया । ये सब नक्सलियों के स्लीपिंग सेल हैं । आतंकवादियों और नक्सलियों के स्लीपिंग सेल हमेशा मौजूद रहे हैं । वामपंथियों के समर्थन की दरकार होने के कारण कांग्रेस हमेशा उन के प्रति नरम रही । भले इन्हीं नक्सलियों ने छतीसगढ में समूचे कांग्रेस नेतृत्व का सफाया कर दिया था। जब इन शहरी नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला कहा, वामपार्टियों ने वही मानवाधिकार हनन और लोकतांत्रिक अधिकारों वाले जुमले दोहराए ।

अपन को वामपंथी विचारधारा के जितने भी प्रोफेसर और पत्रकार दिखते हैं वे सभी नक्सलियों के भी समर्थक होते हैं । वे छतीसगढ, झारखंड, आंध्र प्रदेश में हुई हर नक्सली हिंसा पर किन्तु परन्तु लगा कर समर्थन करते हैं । लोक दिखावे के लिए जनसरोकार जैसे लोकलुभावन शब्दों का इस्तेमाल होता हैं । चुनावी राजनीति में आए वामपंथी रात के अँधेरे में माओवादियों का समर्थन करते हैं । उन्हें हर तरह की मदद भी पहुंचाते हैं । नक्सलियों के स्लीपिंग सेलों की गिरफ्तारी शुरू हुई तो वामपंथी दलों के नेताओं को खुल कर उन के समर्थन में बोलते देखा गया । कांग्रेस और बाकी विरोधी बेचैन हैं पर जितने अरबन नक्सली हैं उतने नहीं । आप इन दोनों की पहचान हिंसक वामपंथियों और कट्टर मुस्लिमों के तौर पर कर सकते हैं। इन दोनों का मकसद भारत से हिन्दू को खत्म करना है । इस लिए जब से राष्ट्रीय विचारों की सरकार आई है, तब से इन का गठजोड़ मजबूत हुआ है ।

जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी (जेएनयू) उन दोनों तरह के भारत तोड़कों की शरण-स्थली है । जेएनयू के वामपंथी किसी भी नक्सली को सुनने के लिए बेताब रहते हैं । पर कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाने वाले अनुपम खेर का विरोध करते हैं । बाबा रामदेव का बायकाट करते हैं । इन्हें अपन शहरी नक्सली कह सकते हैं । जो शहरों में बुद्धिजीवी का चोगा पहने रहते हैं , और पूंजीवाद की खिलाफत के नाम पर नक्सलियों का समर्थन करते हैं । मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं । हैदरावाद में वेमूला के नाम पर फर्जी दलित आन्दोलन इन्हीं का खड़ा किया हुआ था । **भीमा कोरेगांव का हिंसक आन्दोलन भी इन्हीं की साजिश थी ।** सबूत है नक्सलियों की शरण स्थली जेएनयू में भारत तोड़ने के नारे लगना जिस में मुस्लिम आतंकियों और नक्सलियों का गठजोड़ था । वह कमर टूटी भी है, इसलिए इन वर्षों में देश में आतंकवाद की एक भी बड़ी वारदात नहीं हुई ।

पुणे पुलिस ने जून में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था । इन्हीं में से एक के घर से चिठ्ठी मिली थी । **जिसमें मोदी की हत्या भी राजीव गांधी स्टाईल में करने की बात थी ।** एम-4 राइफल व चार लाख चक्र कारतूस खरीदने का जिक्र है । जिस के लिए आठ करोड़ रुपये की जरूरत बताई गई है । चिठ्ठी में वरवर राव का नाम भी लिखा था । स्वाभाविक है कि गिरफ्तारी के बाद वरवर राव ने आरोपों को खारिज किया है। उन का वही जनसरोकार वाला जुमला सामने आया कि पांचों लोग वंचितों की भलाई के लिए काम रहे थे । यह चिठ्ठी किसी 'आर' नाम के व्यक्ति की लिखी हुई है । मुंबई में वेरनन गोन्जाल्विस और अरूण फरेरा के घरों पर छापे मारे गए। तो दिल्ली में भी गौतम नवलखा के घर पर छापा मारा गया । महाराष्ट्र की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाना चाहती थी । पर उनके समर्थकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। **सुनवाई तक नवलखा अपने ही घर में नजरबंद रहेंगे ।**

श्रीकांत पुरोहित को फंसाने की साजिश कहां रची गई , किस ने रची । इस जांच के आदेश तभी हो जाने चाहिए थे, जब सेना ने कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी के तार उन की 2006 में आर्मी की दक्षिण कमांड को सौंपी गई रिपोर्ट

से जुड़े हैं । उन्हें आतंकवादियों, माओवादियों,नक्सलियों की सूचनाए इक्कट्ठी करने की जिम्मेदारी दी गई थी । यह बाकायदा आर्मी के रिकार्ड में था । जिन में घुस कर वह रिपोर्ट दाखिल करने में सफल रहे । 31 दिसम्बर 2006 में सेना की रिपोर्ट् में पुरोहित के काम की तारीफ की गई थी ।

क्या सफेदपौश शहरी नक्सलियों के तार अभी भी सिमी जैसे मुस्लिम आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं । शहरी नक्सलियों की तार धरपकड़ का भी क्या उस रिपोर्ट से ताल्लुक है । सेना की 31 दिस्मबर की रिपोर्ट में सिमी और नक्सलियों के गठजोड़ का जिक्र है।

दाउद ने 2005 में नक्सलियों से सम्पर्क साधा था । यानि 1993 के बम विस्फोटों के बाद वह देश भर में भारत तोडक तत्वों से हिंसक वारदातें करवा रहा था । मुस्लिम आतंकियों के अलावा नक्सलियों के भी सम्पर्क में था । सवाल यह है कि यूपीए राज में अपनी मुम्बई यात्रा के दौरान क्या वह भारत तोडक शहरी नक्सलियों से भी मिला था । रिपोर्ट में कट्टरपंथी मुसलमानों, नेताओं और उदारवादी बुद्धिजिवियों के गठजोड़ का जिक्र है।

साभार- नया इंडिया — ***- अजय सेतिया***

नक्सलियों का शहरी कनेक्शन टूटने पर ही नक्सलियों का खात्मा हो पाएगा। करोड़ों की उगाही की बातों को पूर्व नक्सली फारुक अली ने उजागर किया। उन्होंने कहा कि नक्सली जो कहते हैं कि वे आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। नक्सली आदिवासियों के विकास में सबसे बड़ी रुकावट हैं।

शहरी नक्सल पर भारी हमला

मेरे एक ट्वीट ने सैकड़ों शहरी नक्सलियों को कोठरी से बाहर कर दिया उनमें से ज्यादातर छापे के खिलाफ विरोध कर रहे थे और ऐसे हार्ड-कोर शहरी नक्सलियों का बचाव कर रहे थे। कोई भी भारत के दुश्मन की रक्षा करेगा? लेकिन इससे पहले कि हम उत्तर मांगें, हम छापे और गिरफ्तारी के कारण समझते हैं।

नक्सलवाद का जीवन निर्दोष बच्चों की अशांति, हत्या, विनाश, बलात्कार, आगजनी, लूट और हत्याओं का इतिहास 50 वर्षों से अधिक का रहा है। यह भारत का दुर्भाग्य, हमारे नेताओं के राजनीतिक कौशल, आलसी बुद्धिजीवियों, भ्रष्ट चौथे खंभे, एक निष्क्रिय तंत्र या उन सभी का संयोजन था जो इस नक्सलवाद रूपी राक्षस को बढ़ावा दे रहे है जो भारत की सबसे बडी आतंरिक सुरक्षा के संकट के रूप में उभरा है। सबसे खतरनाक। घातक।। और बर्बर।।।

नक्सलवार, जिसे माओवाद भी कहा जाता है, हमेशा वामपंथियों और उदारवादियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक देश में हिंसक और बर्बर आंदोलन इतने वर्ष कैसे जीवित रह सकता है। आज भारत विश्व में आशाजनक और शांतिपूर्ण राष्ट्रों में से एक हैं। वामपंथी, वे लोग हैं जो शासन, प्रशासन में विश्वास नहीं करते हैं। यह एक और बात है कि आज वे स्वयं भ्रष्ट संस्थान हैं और खुद के खिलाफ आवाज उठाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसलिए, वे इस प्रतिद्वंदी,हिंसक विचारधारा में शामिल ही नहीं, बल्कि उनके आन्दोलन के साथ खुलकर दिखते हैं जो पूरी तरह से छिपे हुए आतंकवादियों, माआवादियों सभी अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी ताकतों द्वारा संचालित है।

इनमें से बहुत से वामपंथी और उदारवादी नक्सल दबाव में हैं और उनके फ्रंट संगठन के रूप में काम करते हैं। उनको क्यों समझ में नहीं आता है कि वे मानवता के सबसे घृणित कृत्यों में लगे होने पर भी स्वयं को उदारवादी कहते हैं? जय साईबाबा, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया था, कुछ जगहों पर उनके रणनीतिक दस्तावेज पाए गए थे। ये

दस्तावेज भारतीय क्रांति के केन्द्रीय कार्य राजनीतिक शक्ति को चंगुल में लेने के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप और दृढता से बताते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए, भारतीय लोगों को सेना के रूप में संगठित किया जाना होगा और उन्हें युद्ध के माध्यम से भारत के सशस्त्र बलों को मिटा देना होगा और लोगों के लोकतांत्रिक राज्य को स्थापित करना होगा। इतना ही नहीं यह विचार शासन व्यवस्था में चला जाता है। देश की सेना, पुलिस और नौकरशाही को नष्ट करके लोगों के प्रशासनिक तंत्र की स्थापना का कार्य, भारत की लोकतांत्रिक क्रांति का मुख्य कार्य है।

यह कैसे प्राप्त किया जा रहा है? वे इसे ग्रामीण इलाकों में पहले क्रांतिकारी आधार क्षेत्रों की स्थापना करके पूरी तरह से समझाते हैं जहां दुश्मन भारत कमजोर है और फिर धीरे-धीरे उन शहरों को पकड़ने और उन पर कब्जा करने के लिए जो दुश्मन के गढ़ हैं। नक्सल जंगली या सामान्य नहीं है। नक्सल स्मार्ट हैं। वे शिक्षित हैं, राजनीति, युद्ध रणनीति और देश की भूगोल को समझते हैं।

जहां परिवहन और संचार सुविधाएं जंगलों में बहुत खराब हैं और दूरस्थ ग्रामीण इलाके सैन्य केन्द्रों से बहुत दूर हैं। जिनसे उन्हें जंगलों में पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, उन्होंने दुश्मन भारत के खिलाफ युद्ध करने के लिए घने जंगलों को अपने मुख्य गढ़ बना दिया है। वे इसे मुक्त क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से वे लोगों के विभिन्न समूहों को उपयोग करके शहरों में दुश्मन भारत पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। मजदूरों से लेकर पत्रकारों, वकीलों, प्रोफेसरों और कलाकारों तक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन छात्रों की अस्थिर प्रकृति है वे उनके लिए हथियारों और गोला बारूद के रूप में काम करते हैं।

अब असल में, मैं उन सभी गुमराह लोगों के साथ पूरी तरह से सहानुभूति व्यक्त करता हूँ जो शहरी नक्सली क्लब से जुड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वे नहीं जानते हैं। ये लोग कैसे कार्य करते हैं। उन्हें लगता है कि शहरी नक्सलवाद असंतोष के लिए एक तरह का आंदोलन है। नहीं ऐसा नहीं है। धीरे-धीरे पुलिस, सेना, नौकरशाही, प्रशासन, कानूनी व्यवस्था और शिक्षा में घुसपैठ करता है। यही कारण है कि शहरी क्षेत्र सशस्त्र क्रांति के लिए मजबूत भर्ती केन्द्रों के

रूप में बने रहेंगे, जबकि भर्ती सामान्य नागरिकों की तरह सामान्य रूप से घूमते रहेंगे। उन्हें भारत के (अदृश्य दुश्मन) बनना चाहिए।

आवश्यक विचारधारात्मक और राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कैडरों को नियमित रूप से शहरों में भेजा जाना है। यह हैं अंशकालिक (पीटी) या पेशेवर क्रांतिकारियों (पीआर) ।

रणनीति बताती है कि ये कबीर कला मंच जैसे शहरी इलाकों में एक फ्रंट संगठन (एफओ) बनाते हैं जो एक सांस्कृतिक संगठन प्रतीक हो सकता है लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भर्ती, ट्रेनिंग और हमला करना है। सोशल मीडिया के आगमन के बाद से, उनकी नई रणनीति पकड़े जाने पर मंद हुई है। सब कुछ धुंधला हो जाता है। आप किसी की पहचान नहीं कर सकते।

यह मीडिया मोबलाइलर की मदद से हासिल किया जाता है। ये मीडिया मोबलाइलर कौन हैं? आप उन्हें बिना किसी पत्रकारिता योग्यता, मजबूत, प्रभावशाली संभावित, कानूनी कार्यकर्ताओं, छात्र नेताओं, और कैडर के साथ मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों का हिस्सा बन जाते हैं। वे कई चेहरों के साथ आते हैं। अरबन नक्सलवाद के लिए भाषण की स्वतंत्रता सबसे सुरक्षित साधन है। इसके अलावा नारीवाद जैसे मुद्दे बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं जो दुश्मन भारत के खिलाफ सामूहिक आंदोलन में मदद करते हैं।

आप सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, कविता लिखने और नारीवादी अभियान चलाने वाले इन मोबलाइजर्स की चैटिंग या चुटकुले पा सकते हैं। कभी-कभी आप उन्हें कांग्रेस या संघी या सिर्फ एक हानिरहित ट्रोल के रूप में देख सकते हैं। लेकिन वे नहीं हैं जो आपको लगता है कि वे हैं। उनका कार्य भारतीय संस्कृति, परिवार और समाज की भारतीय परिभाषाओं पर लगातार सवाल उठाना और उदारवाद व आधुनिकता के नाम पर युवा अनुयायियों को आकर्षित करना है। यदि आप इनके जीवन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप अपने आप को खतरनाक लोगों का शोध करते पाऐंगे। आधुनिक, शिक्षित और तनावग्रस्त शहर के निवासी तनाव से पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। इसका लाभ वे ऐसे तनावग्रस्त किसी भी व्यक्ति को वैचारिक रूप से आकर्षित करते हैं जो

चैंपियन किशोरों की तरह स्वतंत्रता चाहते हैं। जब इन निर्दोष भोले शहरवासियों को (शहरी नक्सल) का समर्थन करने नए नए प्रभावित लोगों को लगता है तो ये स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि शासन शहरी नक्सल का दमन कर रहा है।

उन्हें कभी नहीं पता चलता कि शहरी नक्सल वास्तव में भारत के खिलाफ युद्ध की योजना बना रहा है। इन लोगों को यह नहीं पता कि ये नक्सलवाद के कारण एक व्यक्ति् नहीं ढूंढ सकते हैं जिसका जीवन सुधार हुआ है। हम इससे भी अनजान है कि उनसे जुड़कर के नक्सल वित्त पोषण को थोड़ा सहज बना दिया है। उन्हें क्या पता नहीं है कि अप्रत्यक्ष रूप से और अनजाने में भारत के दुश्मन का समर्थन करके, वे भारत के खिलाफ युद्ध करने के विचाराधारात्मक सहसाजिशकर्ता बन गए हैं। मुझे विश्वास है कि शहरी अभिजातत्य वर्ग निर्दोष हैं जो स्थिति की गम्भीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। और यह बिल्कुल शहरी नक्सल चाहता है। उलझन में, असमंजस में गुमराह किए गए शहर-निवासियों, जिन्हें विचारात्मक रूप से डिगाया जा सकता है, ताकि वे एक बार सोचें कि अच्छी क्रांतिकारी कार्रवाई के हमें कहा जा रहा है।

यह एक रणनीति है। जब एक चोर की पहचान की जाती है तो हर किसी को चोर को बुलाएं और कुछ समय में पुलिस मनुष्यों के महासागर में एक चोर और निर्दोष व्यक्ति के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं होती। तो पुलिस असली चोर को कैसे पकड़ती है? पहले चिल्लाने वाले व्यक्ति को पकड़ों। ऐसा ही खतरनाक # Me TooUrbanNaxal अभियान इस मामले में टिव्टर पर चलाया किसी को पता होना चाहिए कि वास्तविक सुराग वहां स्थित है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन था। उनमें से ज्यादातर निर्दोष और अनजान थे व अधिकतर लोगों को बाद में पछातावा हो सकता है। लेकिन अफसोस है, हम सब यह करते हैं। जब हम अंग्रेजी, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों से हार गए हमारे अदृश्य कॉलोनिजर- यूएसएसआर और केबीजी, और भ्रष्ट सत्ताओं से हार गए, मुगलों से हार गए। पिछले हजार वर्षों से, कुछ बेईमान और गैर जिम्मेदार नागरिकों के कारण, हम हार गए हैं, और पछतावा है। स्वतंत्रता के बाद हम इन अरबन के जाल में किसी को नहीं फंसने दें। **- विवेक अग्निहोत्री**

शहरी नक्सल के खतरनाक मंसूबे

पुणे पुलिस की ओर से कथित 'शहरी नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद देश का ध्यान एक बार फिर भारत के सबसे हिंसक आंदोलन यानि माओवाद की तरफ गया है। माओवाद को भारत में नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर नक्सलवाद के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से ही सबसे पहले माओवादियों ने हिंसक आंदोलन की शुरूआत की थी। अगर यह कहा जाए तो शायद लोग चकित होंगे कि भारत में हिंसक हमलों में होने वाली मौतों में सबसे अधिक मौतों का कारण नक्सली आतंकवाद है। इसमें चकित होने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह एक तथ्य है कि भारत में उग्रवाद से होने वाली सबसे अधिक मौतों का कारण वामपंथी उग्रवाद है। अमेरिका के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सीरिया और इराक में कहर बरपाने वाले इस्लामिक स्टेट और अफगानिस्तान के लिए नासूर बने तालिबान के बाद भारत का नक्सली संगठन विश्व का तीसरा सबसे हिंसक आतंकी संगठन है। इसी कारण नक्सलवाद आतंकवाद का पर्याय बन गया है।

नक्सलवादी आखिर चाहते क्या हैं- इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर है- दो साल पहले जेएनयू में लगा कुख्यात नारा **'भारत तेरे टुकड़े होंगे।'** जाहिर है कि इसके बाद यह सवाल उठेगा कि वे ऐसा क्यों चाहते हैं तो जवाब यह है कि नक्सली भारतीय गणतंत्र और इसके 'बुर्जुआ संविधान को नष्ट कर माओवादी चीन के मॉडल पर कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। हमें इससे परिचित होना चाहिए कि नक्सली 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय 'चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है' का नारा देने वालों की ही जमात हैं। चूंकि उनकी नजर में भारत में कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा एकीकृत भारत है, इसलिए वे सबसे पहले उसे ही छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं। दशकों के सशस्त्र संघर्ष और आतंक के बाद नक्सली इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एकीकृत भारत को परास्त करना असंभव है। वे इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंच गए हैं,

क्योंकि उन्हें यह दिख रहा है कि भारतीय सेना के उनके खिलाफ उतरने के पहले ही उनकी हालत पस्त हो रही है। अब वे भारत के विघटन की फिराक में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेपाल की तरह छोटे-छोटे राज्यों पर कब्जा करना आसान होगा। नक्सलवादी और वामपंथी सैद्धांतिक तौर पर भारत को एक कृत्रिम राष्ट्र मानते हैं। उनकी यह भी समझ है कि भारत एक दमनकारी साम्राज्यवादी संरचना है जिसने उपमहाद्वीप की विभिन्न् राष्ट्रीयताओं पर कब्जा कर रखा है। उनके अनुसार भारत का अस्तित्व ही समस्या की जड़ है और यहां की जनता को गरीबी, भुखमरी और अन्याय से आजादी भारत को राष्ट्र और राज्य के रूप में नष्ट किए बिना नहीं मिल सकती।

वास्तव में यही मौलिक वामपंथी लाइन है और इसी कारण वामपंथियों ने आजादी के पहले न केवल पाकिस्तान बनाए जाने का पुरजोर समर्थन किया था, बल्कि भारत को करीब 30 और हिस्सों में बाँटने की वकालत भी की थी। आज भी वामपंथी किस्म-किस्म के अलगाववादी संगठनों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समर्थन देते हैं और उनकी मांगों को बल प्रदान करते हैं। यह काम सार्वजनिक जीवन में सक्रिय उनका हर वह कैडर करता है जो अकादमिक और साहित्यिक जगत के साथ-साथ पत्रकारिता, गैरसरकारी संगठनों और यहां तक कि कॉर्पोरेट जगत में भी मौजूद है। **यही कैडर शहरी नक्सली है।** इनके मुख्य काम हैं अपने हथियारबंद साथियों को पैसा एवं संदेश पहुंचाना, शहरों में उनके लिए सुरक्षित ठिकाने तैयार करना और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार नक्सलियों को मानवाधिकार व कानून की दुहाई देकर बचाना। इसके अलावा शहरी नक्सली माओवादी विचार और एजेंडे का प्रचार-प्रसार भी करते हैं। इसी क्रम में वे मीडिया और शैक्षिक संस्थानों के जरिए भारतीय शासन व्यवस्था के खिलाफ माहौल भी बनाते हैं।

2009 में कांग्रेसनीत तत्कालीन संप्रग सरकार द्वारा माओवादियों के खिलाफ शुरू किए गए **'ऑपरेशन ग्रीन हंट'** ने जब उन्हें भारी क्षति पहुंचाई तो उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए शहरी इलाकों में अपने विस्तार पर बल देना शुरू किया। इसी के बाद 'शहरी नक्सलियों' की गतिविधियों में

तेजी आई। उन्होंने शहरी इलाकों में अपनी गुपचुप सक्रियता बढ़ाने के साथ ही देश में चल रहे विभिन्न अलगाववादी व जिहादी संगठनों से तालमेल बनाना शुरू किया। पुणे पुलिस की ओर से गिरफ्तार पांच लोगों में शामिल वरवर राव का कहना भी है कि हम सबका दुश्मन एक ही है- दिल्ली।

माओवादियों की समझ से दिल्ली को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका है अलगाववादी ताकतों को मजबूत करना। वे शहरों में संघर्ष और टकराव की स्थिति पैदा करने की फिराक में रहते हैं, ताकि भारतीय राज्य व्यवस्था पंगु हो जाए। अलग-अलग चल रहे आंदोलनों जैसे दलितों, मजदूरों और किसानों के आंदोलन में घुसपैठ करना और उन्हें हिंसक रास्ते पर मोड़ना भी माओवादी रणनीति का अहम हिस्सा है। माओवादी यह मानते हैं कि शहर भारतीय-राज्य और पूंजीपतियों की शक्ति के केंद्र हैं और चूंकि शहरों में ही प्रशासन, न्यायपालिका, विधायिका, सुरक्षा बल आदि की प्रभावी उपस्थिति है, इसलिए वहां अराजकता पैदा करके राज्य के संसाधनों और शासकों का ध्यान शहरों की सुरक्षा में ही फंसा देना चाहिए। उनके अनुसार इससे भारतीय शासन के लिए अलगाववादी ताकतों से सामना करना कठिन हो जाएगा और जब भारत का विघटन यानि 'टुकड़े-टुकड़े' हो जाएंगे तथा दिल्ली की सत्ता एवं शक्ति सिकुड़ जाएगी तो अनिर्णय-अराजकता की हालत में माओवादी अपनी गुरिल्ला सेना के जरिए विभिन्न् हिस्सों पर कब्जा करके कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना कर लेंगे।

यह भी समझना आवश्यक है कि भूमिगत नक्सलियों और उनके शहरी कैडर यानी **शहरी नक्सलियों का दुश्मन मोदी, भाजपा या संघ नहीं, बल्कि भारत है।** दिल्ली में बैठने वाली हर सरकार उनके लिए फासीवादी और जनविरोधी है। इसी कारण प्रधानमंत्री रहते समय मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया था। तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने भी बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ का चोगा पहने शहरी नक्सलियों को भूमिगत नक्सलियों का सुरक्षा कवच बताया था, लेकिन आज कांग्रेस उन संदिग्ध नक्सलियों के समर्थन में खड़े होना पसन्द कर

रही है, जिनमें से कुछ को स्वयं उसकी सरकार गिरफ्तार कर चुकी है।

माओवादियों की नजर में कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, द्रमुक, अन्नद्रमुक अथवा चंद्रबाबू नायडू या ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं है। वे इन सबको या तो लेबर-कैंप में भेज देंगे या लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून देंगे, जैसा कि वे अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में करते हैं। हिटलर तो सिर्फ 50-60 लाख लोगों को मारकर बदनाम है, लेकिन वामपंथियों ने जिन देशों में सत्ता पाई, वहां करोड़ लोग मार दिए। उन्होंने इन सबके खात्मे को जरूरी भी बताया। यह हैरान करता है कि कुछ लोग ऐसे खतरनाक तत्वों का समर्थन केवल इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर मसले पर वर्तमान सरकार का विरोध करना है। इन लोगों ने **मोदी सरकार विरोध और देश विरोध का अंतर खत्म कर दिया है।** उम्मीद है कि सरकार में रहे और नक्सलियों के इरादों से परिचित कांग्रेस सरीखे दल अंततः विवेक से काम लेंगे।

– साभार नई दुनिया

–अभिनव प्रकाश

दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक Urban Naxal कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के बारे में बताया गया।

पोडियाम पांडा ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में अपना दुःख बताया कि मैं पहले अपने गांव का सरपंच था, लेकिन नक्सलियों ने मुझे डरा धमका कर अपने साथ जोड़ लिया। फारुख अली और उनके भाई पर नक्सलियों ने कई बार हमला किया, लेकिन वे लगातार नक्सलियों के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। फारुख अली के भाई नक्सली विरोधी आंदोलन सलवा जुडूम से जुड़े थे, इसलिए उन पर जानलेवा हमला हुआ था।

भारत तेरे टुकड़े होंगे...

नक्सल शब्द को तो हम लम्बे समय से जानते है, किन्तु पिछले कुछ दिनों से ''अरबन नक्सल'' शब्द मीडिया में छाया हुआ है।

फिल्म निर्माता-निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनायी ''बुद्धा इन अ ट्रेफिक जाम'', इसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी ''अरबन नक्सल''। पुस्तक का यह शीर्षक चुन कर इस शब्द का प्रयोग कर इस मुद्दे पर समाज का ध्यान खींचा। तब ही से उन पर वामपंथियों द्वारा लगातार हिंसक और वैचारिक हमले मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं।

नक्सल है क्या? क्या यह बिल्कुल पिछड़े इलाको में गरीबी और अशिक्षा के कारण मौजूद है? क्या यह केवल देश के भीतर की समस्या है? इनके उद्देश्य क्या है? और ''अरबन नक्सल'' क्या है? समझना होगा।

माओस्ते तुंग और ब्लादिमर लेनिन से प्रेरित हिंसक क्रान्ति के द्वारा भारत को एक कम्यूनिस्ट देश बनाना। प्रभावशाली या आमजनों की हत्या, अपहरण आदि करना। सरकारी कर्मचारियों और पुलिस/सेना आदि से सीधे मुठभेड़ करके शासन व्यवस्था पर कब्जा जमाना, यही नक्सलवाद है। **वाम विचार प्रेरित आतंकवाद।** किन्तु इन पिछड़े हुए, अशिक्षित और गरीब लोगों को ऐसा करने के लिए, उकसाता कौन है?

बड़े शहरों के साहित्य, विश्वविद्यालयों, अन्य बौद्धिक मंच, कला, मीडिया, पत्रकार और यहाँ तक कि फिल्म इण्डस्ट्री से जुड़े हुये पढ़े लिखे किन्तु उसी विचार को मानने वाले लोग, जो प्रोपोगेण्डा कर जन असन्तोष को भड़काकर नक्सलवाद के पक्ष में माहौल बनाते हैं। बहुत ही ''ऑर्गनाईज्ड सिस्टम'' के तहत षडयन्त्रपूर्वक ढंग से अपने उद्देश्यों के लिये काम करते हैं। अधिकांशतः किसी न किसी देशी / विदेशी स्त्रोत से भारी वित्तिय सहायता मिलती है।

इन्हीं लोगों को ''अरबन नक्सल'' कहा गया है। पिछड़े इलाको के

नक्सलों की तुलना में यह लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन लोगों के पास पर्याप्त धन और संसाधन होते हैं और अक्सर आमदनी के लिये कोई अन्य पेशा भी नहीं होता है। जनता को बहकाते-भड़काते, समाज में अराजकता फैलाकर व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। अपने विचारों के प्रति विरोध के लिए पूर्णतयाः असहिष्णु होते हैं।

''इस्टेबलिशमेन्ट'' अर्थात व्यवस्था पर कब्जा करना इनका उद्देश्य है। अक्सर विदेशी शक्तियों के इशारे पर कठपुतली की तरह काम करते हुए कानून को भी नियन्त्रित करने का प्रयास करते हैं। यह देश तोड़ने का भी प्रयास करते हैं। जैसे कश्मीर, नागालैण्ड, या मणिपुर आदि को भारत से स्वतंत्र के नाम पर अलग कराना।

जिन गरीब और वंचित लोगों के लिये संघर्ष की बात करते हैं, उन्हें तो शायद ही कभी लाभ होता है। ''अरबन नक्सल'' पिछड़े क्षेत्रों में जाकर इन लोगों को समर्थन देकर व्यवस्था के विरूद्ध भड़काते हैं। भोले-भाले लोग, एक ऐसी कूटनीति, जो उन्होंने कभी भी नहीं देखी, उसका हिस्सा बनकर अज्ञात भविष्य के लिये खुद को झोंक देते है। अशिक्षित और अनुभवहीन लोग ऐसी कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था बनाने के लिये सशस्त्र संघर्ष करने लगते हैं, जो कि स्वयं गरीबों और वंचितों का दमन और शोषण करती है।

यदि सरकार या अन्य संस्था इन गरीब पिछड़े लोगों के लिये कोई विकास कार्य करने का प्रयास करती है, तो शहरी नक्सली उसमें बाधा डालते हैं। दरअसल शहरी नक्सल चाहते ही नहीं कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो। यदि पिछड़ापन है, तो उनकी सफलता निश्चित है।

पिछले लगभग 100 वर्षों के प्रयासों और प्रयोगों में यह साम्यवादी व्यवस्था जो सम्पूर्ण विश्व में असफल हो चुकी है, नक्सल गतिविधियों के माध्यम से भारत में प्रभाव जमाने का प्रयास कर रही है। दुनिया की अनेकों राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्तियाँ, अपने स्वार्थों को लेकर भारत जैसे विशाल राष्ट्र को कई टुकड़ों में बांट देना चाहती है। ''अरबन नक्सल'' उनके ''लोकल'' सहयोगी ही हैं। यह अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम

शहरी नक्सलवाद देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है?

माओवादियों का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है। दूसरा है ताकत से ही सत्ता प्राप्त करो। लोकतंत्र जैसी कोई चीज उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सबसे पहले उनकी योजना होती है कि सुदूर क्षेत्रों में अपना नेटवर्क बढ़ाओ, जहां प्रशासन की पहुँच कम है, लेकिन इस नेटवर्क को चलाने के लिए एक सपोर्ट चाहिए ताकि उनके द्वारा किए गए कुकर्मों पर कोई पर्दा डाल सके, न्यायालय में उनके लिए बहस कर सके। कोई उनके खिलाफ न लिखे। खासकर शहरी क्षेत्रों में इन्होंने अंग्रेजी बोलेन वाले कथित बुद्धिजीवी तैयार किए जो समाज सेवा के नाम पर उनका एजेंडा चलाने वाले लोग शामिल हैं। नक्सली क्षेत्रों से अवैध रूप से जो हजारों करोड़ की उगाही होती है, उनके पैसों से ये लोग महंगी शराब पीते हैं। जो ये शहरी नक्सल हैं, उनको खत्म कर दो, माओवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा । इनको मीडिया में जगह मिलती है इसलिए यह समाज में बने रहते हैं। मूलतः इनकी प्रवृत्ति और प्रकृति अपराधियों की तरह ही होती है।

पर देशद्रोह ही है।

नक्सलवाद मनुष्य के अहंकार की यात्रा है। समाज के शासन, प्रशासन और व्यवस्था सम्भालने के नाम पर दूसरे पर राज करने की कुतित्स लालसा।

अन्त में समस्या का समाधान क्या है? भारत पुनः अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत और वैभव की ओर लौटे। पूर्वजों के दिये जीवन मूल्य जिनके हम उत्तराधिकारी हैं, की पुनर्स्थापना। याद रहे परतन्त्रता अचानक, एक बार में, एक साथ नहीं आती। वह तो आपको धीरे-धीरे, टुकड़े-टुकड़े, थोड़ा-थोड़ा निगलती है।

-मनु त्रिपाठी

बौद्धिक आतंकवाद

भारत शुरू से ही एक उदार प्रकृति का देश रहा है, सहनशीलता इसकी पहचान रही है और आत्मचिंतन इसका स्वभाव।

लेकिन जब किसी देश में उसकी उदार प्रकृति का ही सहारा लेकर उसमें विकृति उत्पन्न करने की कोशिशें की जाने लगें, और उसकी सहनशीलता व अखंडता को खंडित करने का प्रयास हो तो आवश्यक हो जाता है कि वह देश समाज आत्म निरीक्षण की राह को पकड़े।

31 दिसंबर को हर साल महाराष्ट्र के पुणे स्थित भीमा कोरेगाँव में शौर्य दिवस मनाया जाता है। 2017 की आखिरी रात को भी मनाया गया। लेकिन इस बार इस के आयोजन के मौके पर जो हिंसा हुई और खून बहा उसके छींटे सिर्फ भीमा कोरोगाँव या पुणे या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल गए।

क्योंकि यह केवल एक दलित मराठा संघर्ष नहीं उससे कहीं अधिक था, पुलिस के अनुसार जिसके तार नक्सलवादियों से जुड़े थे और इस साजिश में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले वकीलों से लेकर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक जैसे बुद्धिजीवीयों तक के नाम शामिल हैं।

इस आधुनिक दौर में जहाँ नई तकनीक ने पुरानी तकनीक को बदल दिया है वहाँ युद्ध और आक्रमण के तरीके भी बदल गए हैं। अब कलम ने बंदूक की जगह ले ली है और आधुनिकतम हथियार बन चुकी है।

अब आक्रमण देश की सीमाओं पर नहीं देश के नागरिकों के विचारों पर होने लगा है। देश हित में सोचने वाले बुद्धिजीवी वर्ग से इतर बौद्धिक आतंकवाद फैलाने वाले एक वर्ग का भी उदय हो गया है जो जंगलों में कार्य करने वाले हथियारबंद नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं ।

जी हाँ यही है 'अरबन नक्सलाइट्स' शहरी नक्सलवाद यानि वो प्रक्रिया जिसमें शहर के पढ़े लिखे लोग हथियार बंद नक्सलवादियों को उनकी नक्सली गतिविधियों में बौद्धिक और कानूनी समर्थन उपलब्ध कराते हैं। सामाजिक

कार्यकर्ता से लेकर फिल्म मेकर कुछ भी हो सकते हैं। क्या हमें आश्चर्य होता है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जी एन सांई बाबा को उनकी नक्सलवादी गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र की कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है?

युद्ध रणनीतिज्ञ विलियम एस लिंड ने अपनी पुस्तक 'फोर्थ जर्नेशन वारफेयर' में कहा है कि युद्ध की यह रणनीति समाज में सांस्कृतिक संघर्ष के रूप में दरार उत्पन्न करने पर टिकी होती है। इस प्रकार से देश को नष्ट करने के लिए बाहर से आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती वह भीतर ही भीतर स्वयं ही टूट जाता है। शहरी नक्सलवाद भी संस्कृतिक उदारतावाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगा है। कम से कम भीमा कोरेगाँव की घटना तो यही सोचने के लिए मजबूर करती है।

तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर दलितों की एक रैली का 'यलगार परिषद' जैसा नाम (जो एक कठिन और आक्रमक शब्द है) क्या किसी बुद्धिजीवी के अलावा कोई रख सकता है?

सवाल यह भी कि वो कौन लोग हैं जो इस जश्न के बहाने दो सौ साल पुराने दलित और मराठा संघर्ष को जीवित रखने के द्वारा जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं?

क्या हम इसके पीछे छिपी साजिशों को देख पा रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि चूंकि ये लोग खुद बुद्धिजीवी और वकील हैं कोई आम इंसान नहीं तो इन्हें पकड़ना और इन पर आरोप सिद्ध करना इतना आसान भी नहीं होगा। यही कारण है कि जिस केस की सुनवाई किसी आम आदमी के मामले में किसी निचली अदालत में होती वो सुनवाई इनके मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में हुई। इतना ही नहीं लगभग आठ माह की जांच के बाद भी पुलिस कोर्ट से इन लोगों के लिए हाउस एरेस्ट ही ले पाई, रिमांड नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद इस महत्वपूर्ण बात को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि तीसरी बार की सुनवाई के बाद भी प्रशांत भूषण, मनु सिंघवी, रोमिला थापर जैसी ताकतें इन्हें हाउस एरेस्ट से मुक्त नहीं करा पाए।

आज कांग्रेस भले ही इनके समर्थन में खड़ी है लेकिन यह ध्यान देने योग्य विषय है कि दिसंबर 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने नक्सलियों की 128 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था और भीमा कोरेगांव केस में 6 जून और 28 अगस्त को जो दस अरबन नक्सली पकड़े गए हैं उनमें से सात तो इन्हीं संस्थाओं में काम करते हैं। इनमें से अधिकतर पर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं और कई तो सजा भी काट चुके हैं।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 2013 में मनमोहन सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यहाँ तक कहा था कि अरबन नक्सल और उनके समर्थक जंगलों में घुसपैठ किए बैठी उनकी सेना से भी अधिक खतरनाक हैं। एफिडेविट यह भी कहता है कि कैसे ये तथाकथित बुद्धिजीवी मानवाधिकार और असहमति के अधिकार की आड़ लेकर सुरक्षा बलों की कार्यवाही को कमजोर करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेते हैं और झूठे प्रचार के द्वारा सरकार और उसकी संस्थाओं को बदनाम करते हैं। सोचने वाली बात है कि जब ये अरबन नक्सली लोग नक्सलियों को मानवाधिकारों की आड़ में बचाकर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या खुद को उन्हीं कानूनी दाँव पेचों के सहारे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे ?

लेकिन अब धीरे धीरे इन शहरी नक्सलियों और उनके समर्थकों की असलियत देश के सामने आने लगी है और देश की जनता देश के संविधान का ही सहारा लेकर देश की अखंडता और अस्मिता के साथ खेलने वाले इन लोगों के असली चेहरे से परिचित हो रही है।

– डॉ. नीलम महेंद्र

कौन हैं यह लोग

उन्हें हथियार चाहिए, उन्हें पोलित ब्यूरो की अनुमति चाहिए, हिसंक आंदोलनों की सफलता पर एक-दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। कुछ 'करने' के लिए इशारे का इंतजार कर रहे ये लोग कौन हैं? इन पर चुप्पी ओढ़ने वाले कौन हैं? माओवादी का यह घृणित चेहरा ईपीडब्ल्यू जैसी 'कथित' प्रतिष्ठित पत्रिका में कैसे लगातार लिखता रहा! कैसे इनकी भी प्रतिष्ठा बनी रही, बौद्धिकता का भी ब्रांड बना रहा। लेकिन ऐसी चिट्ठी आने के बाद बुद्धिजीवियों का एक तथाकथित तबका ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिससे इन दोनों की प्रतिष्ठा पर जरा भी आंच आए। कारण, भ्रम बनाए रखने से ही दोनों की दुकानें चलनी हैं। इससे पहले कोबाद गांधी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और हेम मिश्र को गढ़चिरौली से। रोना विल्सन की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। ये सेंट स्टीफेंस और जेएनयू जैसे कथित प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े लोग हैं जो इनके और गढ़चिरौली के बीच ताना-बाना बुनते हैं।

इन पर आरोप लगाने से सीताराम येचुरी से लेकर दिग्विजय तक जुबान को लगाम लगा देते हैं। इन की चुप्पी शर्मनाक है। फिर भी नक्सल पर वह चुप हैं? जो न केवल किसी भी हद तक जाने के लिए कुख्यात हैं, बल्कि इसके लिए उतावली भी। ऐसे में यह पूरे देश की जिम्मेदारी है कि जो चीजें दबाई जा रही हैं, उन्हें बाहर निकालें, उनकी पड़ताल में उतरे। **क्योंकि यह किसी एक की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है।** जिस समय देश को इतने व्यापक हित पर विमर्श करना चाहिए था, उस समय मुद्दे से भटकाने का काम! इसे राजनीति में भी एक हिंसक बंटवारे का संकेतक मानना चाहिए। उन्हें जगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे सोने का स्वांग कर रहे हैं। जगना और जगाना तो इस देश को है, क्योंकि ऐसे लक्षणों का प्रतिकार जितनी जल्दी करें, उतना अच्छा। इस देश को जानने का हक है अकादमिक क्षेत्रों में छिपे कौन हैं यह लोग?

साभार-पाञ्चजन्य

– हितेश शंकर

साजिश के सूत्रधार

वरवर राव – 1957 से कविताओं के माध्यम से समाज के कमजोर तबकों में बात करके वामपंथी विचारक वरवर राव वीरासम रिवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं। उन्हें सबसे पहले 1973 में मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें 1975 से लेकर 1986 तक एक से अधिक बार कई मामलों में गिरफ्तार किया गया।

1986 के रामनगर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार होने के बाद 17 साल बाद उन्हें 2003 में इस मामले में रिहाई मिली। 19 अगस्त 2005 को आंध्र प्रदेश सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत उन्हें फिर से गिरफ्तार करके हैदराबाद स्थित चंचलगुडा जेल भेजा गया। बाद में 31 मार्च 2006 को सार्वजनिक सुरक्षा कानून के खत्म होने सहित राव को अन्य सभी मामलों में जमानत मिल गई।

सुधा भारद्वाज – सुधा भारद्वाज एक अधिवक्ता हैं। फिलहाल वह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की विजिटिंग प्रोफेसर और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की राष्ट्रीय सचिव है। वह पिछले 30 सालों से एक ट्रेड यूनियन की प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से मजदूर बस्तियों में काम कर रही हैं। वर्ष 2000 में सुधा भारद्वाज वकील बनीं।

तब से लेकर आज तक श्रम, भूमि अधिग्रहण, वनाधिकार और पर्यावरणीय अधिकार से जुडे ढेरों मुकदमे मजदूरों, किसानों, आदिवासियों और गरीब लोगों के नाम पर लड़े। वर्ष 2001 से बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वकालत कर रही हैं और छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक सदस्य के रूप में मनोनीत है। इसके अलावा कई मानवाधिकार रक्षकों के पक्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी पैरवी करती रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोंडासावली गांव (सुकमा, छत्तीसगढ़) में एक मामले की जांच इनको दी।

अरुण फरेरा– मुंबई स्थित सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओ) की संचार और प्रचार ईकाई के प्रमुख है। उन्हें वर्ष 2014 में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। इसी दौरान

'कलर्स ऑफ केज – ए प्रीजन मेमोर्स' नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें उनके पांच साल तक जेल में रहने का विवरण है।

गौतम नवलखा– मानव अधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार गौतम नवलखा पर भी नक्सलियों से जुड़े होने के आरोप लगते आए हैं। वे 'पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स' और 'इंटरनेशनल पीपल ट्रिब्यूनल ऑन ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इन कश्मीर' जैसे संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। 2010 में वह उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्हें कश्मीर में घुसने से जम्मू-कश्मीर सरकार ने रोक दिया था।

वेरनन गोंसाल्विस –वेरनन गोंसाल्विस मुंबई विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट और रूपारेल और एचआर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं। उन पर नक्सलियों से जुड़े होने का आरोप है। उन पर 20 आरोप थे, लेकिन जेल में छह साल गुजारने के बाद सबुतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया।

आनंद तेलतुंबड़े – इंजीनियर, एमबीए और पूर्व सीईओ रहे आनंद **तेलतुंबड़े दलित आंदोलन** से जुड़े रहे हैं। उन्होंने वामपंथी आंदोलनों और दलित अधिकारों के संघर्षों से जुड़ी कई पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से साइबरनेटिक्स में पीएचडी की है।

फादर स्टेन स्वामी– केरल के निवासी स्वामी 2003 से रांची में रह रहे हैं। वह जन विकास आंदोलन संस्था के संस्थापक हैं। आदिवासियों के मुद्दे पर लगातार लिखते रहे हैं। नक्सलियों के नाम पर जेल में बंद आदिवासियों पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। चाईबासा में जोहार मानवाधिकार संगठन से जुड़े रहे हैं।

सुसान अब्राहम – सामाजिक कार्यकर्ता वर्नान गोंजाल्विस की पत्नी सुसान पेशे से वकील हैं। इनका जन्म केरल में हुआ था। इनके माता-पिता स्कूल टीचर थे। इन्होंने जाम्बिया में पढ़ाई की है। यह नोटबंदी, फर्जी एनकाउंटर के विरोध में और नारी अधिकारों के समर्थन में होने वाले आंदोलनों का हिस्सा रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जीएन साईबाबा और प्रशांत राही की गिरफ्तारी के खिलाफ भी कई सारे लेख लिखे थे। वह जून में यलगार परिषद से संबंधित मारे गए छापे में पकड़े गए कई लोगों से भी जुड़ी रही हैं।

साभार –दैनिक जागरण – ज्योतिरादित्य

अघोषित आपातकाल की सत्यता

जयपुर में आयोजित युवा संसद के उद्घाटन सत्र में श्री दत्तात्रेय होसबले जी से इस संदर्भ में पूछा गया प्रश्न एवं उसका उत्तर

प्रश्न- आपने 1975 में लगाए गए आपातकाल का उल्लेख किया। हम घोषित आपातकाल के बारे में बार-बार चर्चा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है, आज की स्थिति ज्यादा खराब है। मैं इसे अघोषित आपातकाल कहूंगी जहाँ शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज की स्थिति आपात स्थिति है।

उत्तर- आपका यह प्रश्न करना सिद्ध करता है कि आपातकाल नहीं है। अगर आप 1975 के आपातकाल की घटनाओं और प्रभावों से अवगत होते तो यह सवाल नहीं उठता। आप बेहतर समझ के लिए आर्काइव्स से उन दिनों के समाचार पत्रों की जांच कर सकते हैं। उन दिनों प्रिंटिंग प्रेसों पर छापा मारा जाता था और संपादकीय रिक्त छोड़ दिये जाते थे। इन तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस जांच के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्हें अपील करने का अधिकार है और न्यायालय में इनके मामले की सुनवाई भी होगी। अगर न्यायालय उन्हें निर्दोष घोषित करता है, तो वे स्वतंत्र है। आपातकाल के समय, हम न्यायालय में भी नहीं जा सकते थे।

इन तथाकथित बौद्धिकों के पास अपील करने का अधिकार हैं और इन्हें आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए गिरफ्तार किया गया है। असंख्य लोगों को मीसा में बिना किसी भी उचित कारण सलाखों के पीछे रखा गया था। कई लोगों को सिर्फ जेपी आंदोलन में भाग लेने और समग्र क्रांति का समर्थन करने के कारण बन्द होना पड़ा। उन दिनों मैं पोस्ट-ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और 14 महीने जेल में रहा था। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। भारत के तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था किसी को भी आतंरिक सुरक्षा के लिए गोली मारी जा सकती है। जीने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। सरकार का अमानवीय व्यवहार अकल्पनीय था। इस पीढ़ी के लिए 1975 का आपातकाल, पुरानी समय की पुरानी बातें होंगी लेकिन भारत के लिए यह बहुत पुराना नहीं है 1975 में आपातकाल के प्रभावों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

बड़ी हैसियत वाले नक्सली समर्थक

पुणे पुलिस की ओर से माओवादियों अर्थात नक्सलियों के साथ मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों के पक्ष में जिस तरह कुछ विख्यात लोग आनन-फानन में उच्चतम न्यायालय गए और उनके पक्ष में जितने नामी-गिरामी वकील खड़े हो गए उससे आम व्यक्ति का चकित होना स्वाभाविक है। उच्चतम न्यायालय ने उन पांचों को **पूरी तरह मुक्त करने के बजाय उन्हें नजरबंद रखने का आदेश दिया।**

यह सोचने की बात है कि आखिर इन पांचों की कितनी बड़ी हैसियत है कि इतिहासकार रोमिला थापर, अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, माजा दारूवाला, देवकी जैन और सतीश देशपांडे जैसे लोग उनके पक्ष में याचिका लेकर उच्चतम न्यायालय पहुंच गए और उसकी तत्काल सुनवाई भी हो गई। इन पांचों के लिए उच्चतम न्यायालय में जो बड़े वकील पक्ष करने गए उनमें राजू रामचंद्रन, राजीव धवन, इंदिरा जयसिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण भी थे।

वकीलों की इस टोली के सामने केवल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय सत्ता इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। पता नहीं उनकी ओर से इसका पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया जा सका कि पुणे पुलिस जिन्हें गिरफ्त में लेने जा रही है उनके समर्थक उन्हें बचाने के लिए कानून के हर पहलू को आजमाने के साथ यह माहौल भी बनाएंगे कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति आ गई है।

आज जब भारत सरकार के विरुद्ध लिखने-बोलने, सड़कों पर उतरने, समाचार पोर्टल चलाने और जनहित याचिकाओं के माध्यम से सरकारी फैसलों पर सवाल खड़े करने वाले बड़ी संख्या में सक्रिय हैं तब यह नहीं माना जा सकता कि सरकार इन पांचों को अंदर करके असहमति की आवाज दबाना चाह रही है। कुछ लोग ऐसा ही प्रचारित कर रहे हैं।

इसके पहले जून में भी रोना जैकब विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत और सुधीर धवले को गिरफ्तार किया गया था।

उसी दौरान एक झूठा आरोप यह भी उछला कि इस हिंसा में स्थानीय हिंदू नेताओं का हाथ है। पुलिस ने संभाजी भिड़े के शिव प्रतिष्ठान और मिलिंद एकबोटे के समस्त हिंदू एकता अघाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मिलिंद को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो भीमा-कोरेगांव में फैली हिंसा के तार उन लोगों से जुड़ने लगे जो थे तो माओवादी, लेकिन छद्म तरीके से शहरों में दूसरी गतिविधियां करते थे।

माना जाता है कि ऐसे शहरी नक्सलियों की संख्या अच्छी-खासी है। ये नक्सलियों को वैचारिक कवच देने के साथ ही उनकी हर तरह से मदद भी करते हैं। पुणे पुलिस ने कबीर कला मंच के कार्यकर्ताओं के घर पर छापेमारी की तो उसे वहां से ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे वह उन पांच लोगों तक पहुंची जिन्हें जून में गिरफ्तार किया गया था। पुणे पुलिस की मानें तो यलगार परिषद और कबीर कला मंच नामक संगठन वस्तुत: माओवादियों का शहरी मुखौटे हैं और रोना विल्सन तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईंबाबा के जेल जाने के बाद शहरी माओवादियों को निर्देशित कर रहा था। अन्य चार रोना के ही सहयोगी थे और **दलित आंदोलन के नाम से समाज में तनाव और हिंसा पैदा करने में लगे हुए थे।**

एक अन्य पत्र में गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों की कार्रवाई का बदला लेने की बात की गई थी। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में 39 माओवादी मारे गए थे। रोना विल्सन के घर से बरामद एक पत्र नक्सली संगठन सीपीएम-माओवादी के मिलिंद तेलतुंबडे ने भेजा था। उस पर 50 लाख रुपये का इनाम है। इस पत्र में लिखा था कि भीमा-कोरेगांव आंदोलन बेहद प्रभावी रहा।

अराष्ट्रीय शक्तियाँ – कॉमरेड किसन और कुछ अन्य सीनियर कॉमरेड्स ने वर्तमान प्रधानमंत्री को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए हैं। हम सभी राजीव गांधी जैसे हत्याकांड पर विचार कर रहे हैं। हो सकता है हम असफल हो जाएं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे प्रस्ताव पर विचार हो। उन्हें रोड शो में टारगेट करना एक असरदार रणनीति हो सकती है। हमें लगता है कि पार्टी का अस्तित्व किसी भी त्याग से ऊपर है। सरकारी वकील ने न्यायालय में

तीन पत्रों का खास तौर पर हवाला दिया। एक में राउत और सेन का नाम लेते हुए लिखा था कि हथियार खरीदने के लिए आठ करोड़ रुपये की जरूरत है। दूसरे में एक इंस्टीट्यूट के दो लड़कों को प्रशिक्षण देने की बात है। तीसरे में माओवादियों की योजना का विवरण है। इसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ी और फिर पुलिस इन पांचों तक पहुंची।

आज जो कांग्रेस इस मामले में सरकार के खिलाफ आग उगल रही है उसी ने राज्य सरकारों को इनके सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। गिरफ्तार सुरेंद्र गाडलिंग और रोना विल्सन ऐसे ही संगठनों से जुड़े थे। फरेरा और गोंजाल्विस को 2007 में भी पकडा गया था। वरवर राव को तेलंगाना और आंध्र पुलिस कई बार गिरफ्तार कर चुकी है।

हम किसी को अपनी ओर से दोषी करार नहीं दे सकते, किंतु पुलिस अपनी छानबीन से उन तक पहुंची है तो उसे काम करने दिया जाना चाहिए।

– साभार जागरुक टाइम्स – **अवधेश**

नक्सल समर्थक पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं दिल्ली विवि में

बड़े आश्चर्य की बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के विद्यार्थियों को नक्सलियों का समर्थन करने वाली पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। लेखिकाओं नन्दिनी सुन्दर तथा अर्चना प्रसाद की '... बस्तर का इतिहास' तथा ' ... वनवासी पहचान' नाम की पुस्तकों में नक्सलियों की जम कर प्रशंसा की गई है। इसी के साथ वनवासियों को ईसाई बनाये जाने का समर्थन भी इन पुस्तकों में किया गया है।

अब तक ये दोनों पुस्तकें छात्रों को पढ़ाई जा रही थीं। प्रशासन की नींद तब उड़ी जब गत 28 अगस्त को महाराष्ट्र पुलिस ने पाँच शहरी नक्सलियों को बन्दी बनाया। गत अगस्त को पकड़े गये इन नक्सलियों को सुप्रीम कोर्ट ने घर में नजरबन्द रखने के आदेश दिये हैं। नक्सल समर्थक पुस्तकें यदि छात्रों को पढ़ाई जायेंगी तो नये अरबन नक्सली ही पैदा होंगे। –साभार पाथेय कण

शहरी नक्सल-जो भी हैं,. वे कानून के ऊपर नहीं हैं

हमारे देश में थोड़ी देर के लिए, राजनीतिक प्रवचन केवल भावनाओं पर आधारित हैं। हमने वास्तविक तथ्यों की पूरी तरह से अवहेलना कर दी है। कुछ 'शहरी माओवादी आतंकवादियों' की गिरफ्तारी जिन्हें 'शहरी नक्सली' भी कहा जा रहा है, ने निश्चित रूप से इस तरह के राष्ट्रीय विचारों के बहिष्कारों की एक और लहर को जन्म दिया है।

वामप्रेरित मीडिया घरों से राजनेताओं तक, इस मामले के वास्तविक तथ्यों के बारे में किसी भी सवाल को छुपाते हुए, बहस करते हुए कहते हैं कि पुलिस का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। जब कि गिरफ्तार शहरी नक्सलियों के पिछले आचरण पर कोई सवाल उठाया जाता है, तब वे चुनिंदा मुद्दों व जुमलों के भूलभुलैया से भ्रमित करते हैं।

तथाकथित वकील और कार्यकर्ता सुश्री सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने कथित प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आधार पर और उनके असत्यापित अभी तक लोकप्रिय सक्रियता रिकॉर्ड के खिलाफ विशेष रूप से एक बड़ा नाटक किया है। उसके कई सहयोगियों ने गिरफ्तारी में, राजद्रोह जैसे अपराधों तक के प्रयास किए। इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि उसके सहयोगियों को राज्य के खिलाफ कृत्यों को करने के कारण गिरफ्तार या बंद नहीं किया जा सकता है।

जबकि अभी उनके खिलाफ मौजूदा मामला अदालत में लंबित है, हालांकि, कुछ महीनों पहले उनके कई तथाकथित वकील मित्रों और सहयोगियों को ओडिशा के वकील उपेंद्र नायक और महाराष्ट्र के गडलिंग को गिरफ्तार किया गया है।

उनके नाम के साथ एक संगठन या राजनीतिक छवि या पार्टी को

लक्षित करने वाले प्रत्येक साक्षात्कार के एक दर्जन से अधिक वीडियो आ गए। इन वीडियो में किए गए लगभग 90 प्रतिशत दावे पूरी तरह से असत्य हैं और उनमें से अधिकतर के पास कोई तार्किक उत्तर या तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। वह इन वीडियो में दावा करती है कि उनके जैसे लोगों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है जो गरीबों और शोषित लोगों की 'मसीहा' है।

वाम पाखंड स्पष्ट दिखता है और यह बहुत लंबे समय से हो रहा है। दुर्भाग्यवश, राज्य वित्त पोषित संगठन (एनजीओ) इस समय इस तरह के व्यक्तित्वों के समर्थन में आए हैं। एक विधि महाविद्यालय ने दावा किया है कि एक बयान जारी किया गया है –

''सुधा भारद्वाज हमारे पेशे में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण – सरकारी कानूनहीनता की निडर आलोचक, एक आक्रमक और सहानुभूति रखने योग्य वकील है जो उन लोगों की आवाज़ को बढ़ाती है जो शायद ही कभी सत्ता के गलियारे में सुनाई देते हैं, उनकी वकालत, उनकी शिक्षा और उनके जीवन के माध्यम से समाज में परिवर्तनीय भूमिका का उदाहरण हैं। हम केवल हमारे काम और हमारे दैनिक जीवन में बहादुर, अंतर्दृष्टिपूर्ण और ईमानदार होने की उम्मीद कर सकते हैं। सुधा भारद्वाज जैसे नागरिकों के कारण हमारा लोकतंत्र रहता है और बढ़ता है।''

''श्रम कानून, विकास, पर्यावरण, महिलाओं के अधिकारों और न्याय गरीबों तक पहुंचने में उनका व्यापक योगदान है सुधा भारद्वाज को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राज्य न्यायिक अकादमियों में आमंत्रित किया है, और छत्तीसगढ़ राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निकाय में भी नामित किया है।

जबकि इस विधि महाविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों द्वारा किए गए दावे अविश्वसनीय है। भारद्वाज निश्चित रूप से कानूनी पेशे में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं है और यह बिल्कुल स्पष्ट है जिस तरह से वह गर्व से माओवादी टैग पहनने वाले लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध में रही है, और वे लोग हमारे सैनिकों की मौत पर खुश हुए हैं और जिन लोगों ने कश्मीर पर दावा किया है उन्हें भारत से स्वतंत्र होने की अनुमति दी जानी चाहिए। इनको पुलिस और अन्य एजेंसियों की आलोचना करने के बजाय उन्हें सिस्टम का पालन करना चाहिए और अपने

फैसलों का इंतजार करना चाहिए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि विरोध किसी भी लोकतांत्रिक समाज में नागरिकता का मूल अधिकार है, इसलिए हमारे पास सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि आलोचना केवल लोगों और उनकी नीतियों तक ही सीमित होनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र हमारे देश की बुनियादी नींव के लिए कोई खतरा नहीं बनना चाहिए और वामपंथीवाद का विचार इस के खिलाफ है।

साभार- यूथ की आवाज ***-शौर्य रंजन, दिल्ली विश्वविद्यालय***

यह होता है पोलित ब्यूरो

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर नीति निर्धारक होती है पोलित ब्यूरो। समाज को जाति के आधार पर बांटने वाली राजनीति में कम्युनिस्ट कैडर का दिखना आम है। इनके चरित्र का दोहरापन 2015 के पोलित ब्यूरो के सदस्यों के नाम की सूची आते ही पूरे देश ने देखा। लंबी सूची में एक भी नाम दलित वर्ग से नहीं था, जबकि भारत में इनकी राजनीति का आधार ही जाति है। अप्रेल में कम्युनिस्ट पार्टी की 22 वीं कांग्रेस हुई, जिसमें अगले 3 सालों के लिए सीताराम येचुरी महासचिव निर्वाचित हुए। केन्द्रीय समिति के 95 सदस्यों ने उन्हें दूसरी बार इस पर चुना है। पोलित ब्यूरो में वर्तमान में 17 सदस्य हैं, सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, रामचन्द्रन पिल्लै, बिमान बसु, मणिक सरकार,वृंदा करात, पिनरई विजयन, हन्नान मोला, कोडियारी बालकृष्णन, एम.ए. बेबी, सूर्याकांता मिश्रा, मोहम्मद सलीम, सुभाषिनी अली, बी.वी.राघवलु, जी. रामाकृष्णन, तपन सेन ओर नीलोत्पल बसु।

घातक गठजोड़

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-माओवादी (सीपीआईएम) का एक आंतरिक पत्र महाराष्ट्र पुलिस के हाथ लगता है।

कहानी और पुरानी है। यलगार परिषद का एक ड्रामा होता है। बताया जाता है कि यह दलितों का कोई मामला है, जिसमें 'डांस-ड्रामा' हुआ था और चार मटके फोड़े गए थे। असली खेल अगले दिन, हिंसा का तांडव रचा गया और उसके बारे में बड़े-बड़े झूठ गढ़े गए। हर झूठ का पर्दाफाश हुआ, हालांकि थोड़ा समय लगा। इस हिंसा के संबंध में दो एफआईआर दर्ज हुईं, तमाम तफ्तीश हुई।

ई-मेल में सीआरपीसी की बैठकें बार-बार बुलाने की बात कही गई है। यह रोचक और आँखें खोलने वाली बात है। 'सीआरपीसी' माने तमाम भारत विरोधी अपराधियों, देशद्रोहियों के बचाव के लिए बनाया गया एक नक्सली मंच। पूरा शब्द है-कमेटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और कमेटी की आड़ में कश्मीर के आतंकवादियों की वकालत की जाती है, ऑस्ट्रेलिया में खदान खरीदने के भारत के अडानी समूह के प्रयासों का वहां विरोध किया जाता है (जिसे अंततः चीन खरीद लेता है और इस इस उद्देश्य के पूरा होते ही विरोध भी बंद हो जाता है) तमिलनाडु के तुतुकुडी में स्टारलाइट के तांबा गलाने के संयंत्र के खिलाफ साजिशों को लेकर देश के खिलाफ दूसरी अन्य साजिशों की लम्बी सूची मंच की कारगुजारियों में शामिल है।

पत्र में किसी कॉमरेड सिराज का जिक्र है और यह बेहद सनसनीखेज है। सिराज को एक बार कॉमरेड सिराज कहा गया है, दूसरी बार सिर्फ सिराज कहा गया है। एक ओर कहा गया है कि वह 'हर संभव तरीके से पार्टी की मदद के लिए तैयार हो गया है' और दूसरी और कहा गया है कि वह कई वर्षों से पार्टी का साहित्य और संविधान पढ़ता आ रहा है।

एक और सनसनीखेज बात। पत्र के मुताबिक -सिराज चुनौतीपूर्ण

परिस्थितियों के बावजूद, दूसरे एपीटी के 'क्रासओवर' के लिए तैयार हो गया है। 'क्रासओवर' माने सीमापार ? कहाँ से ? किस दिशा से ? और कौन भेज रहा है? अगर आप सीआरपीसी को गूगल करते हैं तो इनमें से अधिकांश सवालों का जवाब आपको मिल सकता है। सरलता के लिए आप सीआरपीसी के साथ-साथ सीपीआईएमएल भी लिखें।

आगे का विवरण उतना छिपा हुआ नहीं है। पत्र में लिखा गया है कि 'पिछली बार सौदा करने के लिए कॉमरेड बसंत से विष्णु की बात हुई थी... बाकी तो आप जान ही गए होंगे और अब एम-4 राइफल और 4 लाख राउंड की सालाना खरीद के लिए रू. 8 करोड़ की आवश्यकता है।

जाहिर तौर पर हथियारों की खरीद का मामला बहुत गंभीर है, हालांकि पत्र यह भी स्वीकार करता है कि ''परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं।'' पत्र में आगे लिखा गया है कि ''हिन्दू फासीवाद को हराना हमारा मुख्य एजेंडा और पार्टी के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है।... हम देश भर में समान विचार वाले संगठनों, राजनीतिक दलों, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।''

पत्र में आगे की चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसी बिन्दु पर बात करें। तमिलनाडु के तुतुकुडी में स्टरलाइट के तांबा गलाने वाले संयंत्र के खिलाफ साजिशें और हिंसा में नक्सलियों और चर्च की भूमिका सबके सामने है। लेकिन उसे मुख्यधारा के एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के अपने टवीट में 'स्टेट स्पांसर्ड टेररिज्म' भी कहा था, और कहा था कि ''आरएसएस'' की विचारधारा न मानने के कारण .... यह हिंसा हुई है।''

अब फिर से गौर करें। पत्र में कहा गया है-

1. ''हिंदू फासीवाद को हराना हमारा मुख्य एजेंडा है... और राहुल गांधी कहते हैं कि ''आर एस एस की विचारधारा न मानने के कारण ... यह हिंसा हुई।'' जो उनकी समझ में 'हिन्दू फासीवाद' है। कितना नजदीकी तालमेल है।

2. पत्र में कहा गया है-''हम देशभर में समान विचार वाले संगठनों, राजनीतिक दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।'' और कांग्रेस और

कम्युनिस्ट पार्टियां तुतुकुडी के गुंडों का तुरंत समर्थन करती हैं। कितना नजदीकी गठजोड़ है।

3. पत्र में कहा गया है- '' हम अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्वों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। '' और कश्मीर में आतंकवाद के समर्थक और जिहादियों से लेकर चर्च की तुतुकुडी हिंसा में संलिप्तता छिपाए नहीं छिपती।

दर्द कहां है? पत्र में गौर से आगे देखें। पत्र में कहा गया है- ''मोदी ने बिहार और पं.बंगाल जैसी बड़ी पराजय दी है। स्वाभाविक है बांग्लादेश सीमा पूरी तरह सीज हो गई है। पाकिस्तान जिस गति को प्राप्त हो चुका है, उसके बारे में विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। नक्सलियों की 'टुकड़े-गैंग' खुद टुकड़े-टुकड़े हो गया है। परेशानी सिर्फ 'बेहद' नहीं, 'बेहद-बेहद' है।

और इस पत्र को पकड़ा गया भीमा-कोरेगांव की हिंसा के सिलसिले में की गई गिरफ्तारी के दौरान। पुलिस ने पेनड्राइव, हार्डडिस्क और कुछ अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पैसों, हथियारों की आवाजाही की साजिश, और बाकी जो भी चीजें एक आतंकवादी संगठन के संचालन के लिए जरूरी होती है, उन सबके तार यलगार परिषद से जुड़े पाए गए हैं। आज के दौर में तो नेटवर्क से नेटवर्क जुड़ते हैं। इटली से लकर पाकिस्तान तक। कैसे? आइए देखते हैं। जब आप आईसीएसपीडब्ल्यूइंडिया डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम पर पहुँचेंगे तो मुखपृष्ठ पर ही आपको सबसे मुख्य लिंक मिलता है, उसमें कहा गया है- फ्रॉम इटली टू द वर्ल्ड...। फिर इटालियन भाषा में कहा गया है- भारत की फॉसिस्ट और साम्राज्यवादी हुकूमत के बारे में जानकारी यहां डाउनलोड करें। और पाकिस्तान? तार से तार जुड़े होने के कई इशारे मौजूद हैं। इशरत जहां और सोहराबुददीन जैसी कोशिशों को परे रख दें, तो 27 अक्तूबर 2013 की पटना में मोदी की हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार विस्फोट किए गए। छह व्यक्ति मारे गए और अन्य घायल हो गए। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आतंकवादियों ने गांधी मैदान स्थल पर 9 बम लगाए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान (फरवरी

2017) प्रधानमंत्री के काफिले पर राकेट लांचर और विस्फोटकों से हमला करने की साजिश थी, जिसे समय पर नाकाम कर दिया गया, साजिश रसूल पति गिरोह की थी। फिर चार महीने बाद, केरल में नई मेट्रो लाइन के उद्घाटन के असवर पर प्रधानमंत्री पर हमला करने की आतंकवादी साजिश भी समय रहते पकड़ी गई। केरल पुलिस में महानिदेशक ने खुद इस साजिश के बारे में मीडिया को बताया है। पकड़े गए पत्र में स्वीकार किया गया है कि 'राजीव गांधी जैसी' साजिश आत्मघाती भी है, और विफल भी हो सकती है। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए।

साभार-पाञ्चजन्य **-ज्ञानेन्द्र भरतिया**

ये है शहरी नक्सलियों के नेटवर्क

बस्तर के आईजी रहे एसआपी कल्लूरी जब 20 मई 2017 को दिल्ली स्थित पत्रकारिता संस्थान आईआईएमसी में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क कर परतें उधेड़ रहे थे, उसी दौरान नक्सलियों के शहरी नेटवर्क में सक्रिय हुई कथित महत्वपूर्ण चेहरे संस्थान के दरवाजे पर कल्लूरी का विरोध करते हुए पाए गए। ये वही लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कथित तौर पर संघर्ष करते हैं लेकिन ऐसे किसी भी स्वर को सुनने को तैयार नहीं होते तो उनकी हत्या की राजनीति पर सवाल उठाए! पुलिस की जानकारी रोना जैकब विल्सन नक्सलियों के ऐसे ही शहरी नेटवर्क का मानवाधिकारवादी चेहरा है।

शहरी नक्सलवाद का असली चेहरा

महाराष्ट्र पुलिस ने फादर स्टन स्वामी, सूजन अब्राहम एंड आनंद तेलतंबड़े के ठिकानों पर छापे मारने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ चुकी है, जिनमें समर्थक और प्रतिवादी साफ पहचाने जा सकते हैं।

ये पूरी बहस छिड़ी है अरबन नक्सल (शहरी नक्सलवादी) शब्द पर। इस शब्द को हमारे शब्दकोश में लाने के लिए मेरे मित्र विवेक अग्निहोत्री और उनकी पुस्तक का धन्यवाद् । संयोग है कि उस पुस्तक का प्रस्तावना मैंने ही लिखी है।

एक विशेषण किसी कहानी की पराकाष्ठा या लघु उपन्यास का मूल सार ही बन सकता है। 'अरबन नक्सल' वैसा ही शब्द है। यह हमें सोचने समझने पर मजबूर करता है कि नक्सलवाद या सही शब्दों में माओवादी विद्रोह सिर्फ दूर-दराज के इलाकों, घने जंगलों या देश के पिछड़े कोनों तक ही सीमित नहीं , अपितु इसकी नींव शहरों तक में गहरी पड़ी है, जहाँ इनको हवा पानी देने वालों में बुद्धिजीवी, मीडिया और वकालत में जुड़े लोग हैं। विवेक की पुस्तक इसी कड़ी को खोजने में सहायता करती है और इस लिहाज से शहरी माओवाद पर ये बहस काफी लम्बे समय से बाकी थी।

कभी-कभी ऐसा नाम या शब्द हमें असल मुद्दे से भटका भी देते हैं। इस मुद्दे पर जो लोग तलवारें खेंचकर खड़े हैं और अपने मतभेदों में सोशल मीडिया पर युद्ध कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। ऐसा कैसे हुआ कि यह सभी कार्यकर्ता जाँच एजेंसी के निशाने पर आ गये? वास्तव में 8 जनवरी, 2018 को तुषार रमेश दशमुंडे ने कबीर कला मंच के खिलाफ एक एफआईआर करायी थी। दमगुंडे 31 दिसम्बर 2017 को एल्गार परिषद के एक सभा में गये थे जहाँ उन्हें उकसाने वाले भड़काऊ भाषण सुनने को मिले।

भीमा कोरेगांव में दंगे भड़के। करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। संघर्ष में चोट खाने वालों में आम लोगों के साथ कई पुलिस अधिकारी भी थे

और एक नौजवान की मृत्यु हो गई। अनेकों प्रत्यक्षदर्शियों ने षडयंत्र का अंदेशा जताया। जिसका उद्देश्य जातिगत हिंसा फैलाना और एक विशेष पार्टी भाजपा के खिलाफ लोगों में रोष पैदा करना था जिसकी केन्द्र और राज्य दोनों में सरकार है।

कबीर कला मंच यूपीए सरकार के दौरान भी शक के दायरे में था। दमगुड़े, जिन्होंने एफआईआर करवाई वो कहते हैं '' मैं एल्गार परिषद में विभिन्न वक्ताओं को सुनने गया था, मैं यह जानता था कि कबीर कला मंच के कई कार्यकर्ता नक्सल गतिविधियों से जुड़े होने के कारण जेल में हैं। सभा के बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। इन लोगों ने सुरक्षा बलों के जीप और ट्रकों को उड़ा दिया। एफआईआर में सुधीर धवाले, सागर गोखले, हरशाली पोतरद, रमेश गैचोर, दीपक देंगले और ज्योति जगताप का नाम है।

हमें भारत की न्याय-प्रणाली पर भरोसा होना चाहिये जो बिना किसी ठोस सबूत के किसी व्यक्ति को सजा नहीं देगी।

साभार- डी.एन.ए. **-मकरंद परांजपे**

ऐसे ही एक अरबन नक्सली चेहरा है मेघा पाटकर जो नर्मदा बचाओ आन्दोलन के नाम पर अराष्ट्रीय विचारों का प्रचार करती हैं तथा जिन मां नर्मदा ने उनको पहचान दी उनके लिए वैश्या जैसा शब्द उपयोग करने में भी नहीं हिचकी, मध्य भारत के किसानों के विस्थापन की आड़ लेकर भड़काने का कार्य करती रहती है।

अरबन नक्सली अग्निवेश

अग्निवेश द्वारा दिए गए भाषण और इसके बाद उनके साथ हुई मारपीट की घटना के बाद अग्निवेश सुर्खियों में बने हुए हैं। जो हुआ गलत हुआ। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, और यदि सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति या संगठन कानून हाथ में लेने की कोशिश करे तो उसकी हर स्तर पर भर्तस्ना होनी चाहिए, उसका सतत विरोध किया जाना चाहिए. हालांकि ऐसा करते समय हमें यह अवश्य पता होना चाहिए कि आखिर दोषी कौन है और घटनाओं के मूल में आखिर है क्या?

झारखंड के उत्तरी इलाके में पाकुड़ जिला है, जहां स्वामी अग्निवेश पहुंचे थे, वहां उन्होंने सनातन धर्म, संस्कृति आदि को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कीं। इसका साक्ष्य वह वीडियो है जो इंटरनेट पर इस घटना के बाद से वायरल हुआ है।

इंटरनेट पर दोनों वीडियो मौजूद हैं पहला जिसमें अग्निवेश सनातन धर्म और संस्कृति अपने शब्द बाणों से घातक प्रहार कर रहे हैं तो दूसरी वह जिसमें उनके साथ मारपीट की गई। उनके कपड़े फाड़ दिए गए। पगड़ी उछाल दी गई। हमले के बाद अग्निवेश ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले भाजयुमो के लोग थे। हालांकि आरोपित पक्ष का कहना है कि वे केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचे थे। उनके साथ जो हाथापाई हुई उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है।

झारखंड शासन के मंत्री सीपी सिंह के इस बयान के बाद मामला और संदेहास्पद हो गया जिसमें उन्होंने अधिकृत रूप से, सुर्खियां बटोरने के लिए स्वामी पर ही हमले की साजिश कराने का आरोप लगाया। बकौल मंत्री श्री सिंह 'अग्निवेश एक धोखेबाज है। मैं उन्हें पिछले 40 वर्षों से जानता हूं। उन्होंने ही स्वयं पर हमले की साजिश रची थी। श्री सिंह ने इसके अलावा विदेशी फंड लेकर प्रदेश-देश को अस्थिर करने का आरोप भी श्री अग्निवेश पर लगाया।

झारखंड सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। निश्चित तौर पर जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचना संभव होगा लेकिन न तो अग्निवेश पर लगाए गए आरोप नए हैं, और न ही इनके साथ हुई मारपीट की घटना ही पहली है। इससे पहले भी गुजरात के सूरत में एक संत ने माला पहनाने के बहाने सरेआम मंच पर ही स्वामी को पीट दिया था। अगर आप अग्निवेश के समूचे सार्वजनिक जीवन पर नजर डालें तो यह कह सकते हैं कि स्वामी ने काफी मेहनत से देश की नफरत फैलाई है।

हर ऐसे किसी विमर्श के समय यह सवाल अनसुलझे ही रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जब भी कहीं देश के खिलाफ कुछ बात होगी, जब भी धर्म और संस्कृति के खिलाफ कहीं कोई साजिश रची जा रही हो, वहां उसके अगुआ या उसके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोगी के तौर पर भगवा बाना पहने स्वामी अग्निवेश ही सबसे मुखर और अगली पंक्ति में दिखते है। भगवा वस्त्र का उल्लेख खास तौर पर इसलिए भी जरूरी है कि जिस आर्य समाज का होने का दावा वे करते हैं, खुद उस समाज ने ही उन्हें इनके ईसाई होने और आर्थिक गबन के आरोप में अपने समाज से निकाला हुआ है।

अन्ना आन्दोलन के समय ही तथ्यों के साथ अग्निवेश के ईसाई होने के आरोप का खुलासा हुआ था, जिसका कोई खंडन आज तक अग्निवेश की तरफ से नहीं आया। उसी समय कांग्रेस सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे के आन्दोलन का चेहरा बने अग्निवेश एक स्टिंग में कांग्रेस के लिए ही काम करते हुए, आन्दोलन को खत्म करने की साजिश करते हुए कैमरे पर रिकॉर्ड हो गए थे। उसी समय उन्हें आन्दोलन से निकाल दिया गया। इसके बाद से वह ओझल हो गए थे। इस घटना ने इन्हें वर्षों बाद फिर से सुर्खियों में आने का अवसर दिया है। बता दें कि बस्तर में नक्सलियों की मांद में उनके साथ 'लाल सलाम' का नारा लगाते हुए भी अग्निवेश पकड़े गए थे। छत्तीसगढ के आदिवासियों ने भी उन पर हमला किया था।

एक बार कुछ प्रसिद्ध गांधीवादी नेताओं ने अग्निवेश को आदिवासियों पर होते कथित जुल्म के खिलाफ पदयात्रा करने बस्तर बुलाया था, जल्द ही उन

सभी लोगों को अग्निवेश की असलियत पता चल गई। सभी लोगों ने अग्निवेश पर आन्दोलन का नेतृत्व हड़पने, चुनावी एजेंट बन जाने और कांग्रेस नेता चिदंबरम का आदेश-पालन करने वाला बताते हुए सार्वजनिक पत्र द्वारा अग्निवेश के किसी भी कार्य से खुद को अलग कर लिया था। सभी गांधीवादी नेताओं ने अग्निवेश को राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उनका इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया था। हरियाणा के पूर्व मंत्री और कुछ वर्ष पहले एक नई पार्टी के गठन की असफल कोशिश करने वाले अग्निवेश अंततः अपनी देश संस्कृति का अपमान करने के कारण ही सभी का इस्तेमाल करते हैं।

ऐसे संदेहों-साक्ष्यों की असंख्य श्रृंखला है जो स्वामी जी को संदिग्ध बताती है लेकिन, हर तरह के ऐसे भंडाफोड़ के बाद कुछ समय शांत रहकर अग्निवेश फिर से लोकलाज छोड़ किसी नए मिशनरी मिशन पर लग जाते हैं, जाहिर है वह मिशन किसी न किसी तरह से देश को कमजोर करने वाला, धर्म और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला ही पाया जाता है।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के एक दक्षिण भारतीय परिवार में पैदा हुए अग्निवेश ने अपने तेलगू भाषी होने का फायदा उठा कर आन्ध्र-बस्तर में सक्रिय नक्सली नेताओं से संपर्क बढ़ाया। लगातार वे माओवादियों के हिंसक अलगाववादी आन्दोलनों को प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से मजबूत करते रहे। कभी अमरनाथ यात्रा को लेकर आन्दोलन हुआ तो वहां भी आर्यसमाजी होने की हैसियत से बयान देने पहुंच गए जिसका फिर से आर्य समाज को खंडन करना पड़ा। कभी उड़ीसा में अगर माओ-मिशनरी पर संकट आया तो वहां भी उनके पक्ष में खड़े दिखे।

जहां तक झारखंड के उनके हालिया कार्यक्रम का सवाल है तो वहां वे एक अनाम से संगठन 'भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति' के आमंत्रण पर पाकुड़ पहुंचे थे। वहां के पहाड़िया जनजाति समाज द्वारा सदी भर से मनाये जाने वाले उत्सव 'दामिन एकोह' में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेना था। झारखंड के जनजाति विषयों के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार दिव्यांशु कुमार बताते हैं कि - ''झारखंड के उत्तरी इलाके की पहाड़िया जनजाति, प्रदेश की

अन्य जनजातियों की तरह ही प्रखर देशभक्त है। मिशनरियों की लाख कोशिशों के बावजूद भी सबसे कम मतांतरण इसी जनजाति में हुआ है। वे सनातन परंपरा के अंग रहे हैं। कुल 1356 वर्ग मील में फैले इस इलाके को वे सौरिया देस कहते हैं, यानी भारत का एक अनोखी एवं विशिष्ट संस्कृति वाला अंचल। आज भी पहाड़िया लोग आधुनिक बुराइयों से दूर और सीधे सरल राष्ट्रभक्त हैं।'' इसी जनजाति के कुछ नव मतांतरित लोगों द्वारा चर्च की मदद से स्थापित संगठन के बुलावे पर अग्निवेश यहां दक्षिण झारखंड/ उत्तर छत्तीसगढ़ की तरह **पत्थलगढ़ी** जैसे आन्दोलन को हवा देने आए थे।

बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हों की तरह ही पहाड़िया जनजाति में भी एक से एक राष्ट्रभक्त नायक हुए हैं। ऐसे ही एक नायक थे मदरा पहाड़िया। उनके नेतृत्व में इस समाज को यह गौरव हासिल है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर अपने इलाके को अंग्रेजों से 'मुक्त' जैसा करा लिया था। उन्हें किसी भी तरह का टैक्स बर्तानिया हुकूमत को नहीं देना है, ऐसा समझौता करने पर अंग्रेज विवश हो गए थे। उस विजय के प्रतीक के तौर पर मनाए जाने वाले उत्सव को राष्ट्र के खिलाफ आन्दोलन के रूप में बदल देना, देशभक्त उत्सव को भारत के खिलाफ ही खड़ा करने का षड्यंत्र इस कार्यक्रम का लक्ष्य था।

जब भी कभी ईसाई मिशनरियां दबाव में होंगी तो उसके तारणहार के रूप में अग्निवेश का पहुंचना नया नहीं है। झारखंड मिशनरी ऑफ चैरिटी में नवजातों को बेचे जाने का खुलासा होने के बाद मिशनरियां दबाव में हैं। एजेंसियों की पैनी नजर सभी मिशनरियों पर बनी हुई हैं। प्रदेश की सरकार भी लगातार इन अपराधिक कुकृत्यों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी तरह अभी प्रदेश के खूंटी में एक स्कूल में पांच आदिवासी बालिकाओं के खिलाफ बलात्कार की घृणित घटना और उसमें चर्च के फादर की संलिप्तता के कारण भी तेजी से मिशनरी एक्सपोज हो रही हैं, जाहिर है ऐसे समय में स्वामी अग्निवेश का वहां सक्रिय होना महज संयोग तो नहीं कहा जा सकता।

अफसोस की बात है कि कांग्रेस समेत झारखण्ड के तमाम विपक्ष को जहां उन पीड़ित आदिवासी बालिकाओं के पक्ष में खड़ा होना था, वहां वे

'फादर' के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ ही आवाज उठाकर अपराधियों-आरोपियों को प्रश्रय दे रहे हैं। यहां तक की बलात्कार के खिलाफ शासन द्वारा की गई कारवाई के खिलाफ संयुक्त विपक्ष राज्यपाल को ज्ञापन देने भी पहुंचा था। और यही विपक्ष एक साथ स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले के अगले दिन प्रेस क्लब पहुंचा। कुछ ही घंटे पहले हुए हमले के बाद पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे 78 वर्षीय स्वामी वहां भी खुद पर किए गए हमले से ज्यादा कथित ईसाईयों के खिलाफ तथाकथित शासकीय जुल्मों पर ही बोलते रहे, जाहिर है स्वामी जी के एजेंडे में तब भी मिशनरियों का संरक्षण ही महत्वपूर्ण रहा।

अग्निवेश पर हुए हमले के बाद युवा मोर्चा के कुल नौ कार्यकर्ताओं को अभियुक्त बनाया गया है। सचाई तो खैर जांच के बाद सामने आएगी ही। निश्चित ही दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए लेकिन, जरूरत इस बात की भी है कि देश के भीतर पल रहे राष्ट्रविरोधी, धर्म विरोधी तत्वों के खिलाफ भी गहरी पड़ताल हो और देश को कमजोर करने की साजिश में लगे लोगों का घिनौना चेहरा जनता के सामने आए।

आज बड़े ही संगठित तरीके से भारत की धर्म-संस्कृति को नष्ट करने की जो साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ सतत जागृति ही हमारा युगधर्म होना चाहिए। हालिया घटनाक्रमों ने राष्ट्रविरोधी हरकतों पर अनेक कोण से हमें सोचने-समझने-सावधान होने का अवसर दिया है।

विश्व संवाद केन्द्र **– विनय**

जे एन यू में पनपती पंखुड़ियाँ

एक था कम्युनिस्ट ..... नाम था कामरेड सज्जाद जहीर .....लखनऊ में पैदा हुए। ये मियाँ साहब ,पहले अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के रहनुमा बनकर उभरे और अपनी किताब 'अंगारे' से इन्होंने अपने लेखक होने का दावा पेश किया ..... बाद में ये जनाब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वेसर्वा बने , मगर बाबू साहब की रूह में तो इस्लाम बसता था, इसीलिए 1947 मे नये इस्लामी देश बने, पाकिस्तान मे जाकर बस गये, इनकी बेगम रजिया सज्जाद जहीर भी उर्दू की लेखिका थी .....।

सज्जाद जहीर, 1948 में कलकत्ता के कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में भाग लेने कलकत्ता पहुँचे और वहाँ कुछ मुसलमानों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर सीपीपी यानि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान का गठन कर लिया, जो बांग्लादेश में तो फली - फूली .....।

मगर पाकिस्तान में सज्जाद जहीर मशहूर शायर लेखक फैज अहमद फैज, शायर अहमद फराज , रजिया सज्जाद जहीर ,और कुछ पाकिस्तानी जनरलों ने मिलकर रावलपिंडी षड्यंत्र केस में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का प्रयास किया और पकड़े जाने पर जेल मे डाल दिये गये । सज्जाद जहीर, अहमद फराज और फैज अहमद फैज को लंबी सजाऐं सुनाई गईं.....

जेल से रिहा होने के बाद सज्जाद जहीर भारत आया और खुद को शरणार्थी घोषित करके कांग्रेस सरकार से भारतीय नागरिकता माँगी ..और कांग्रेस सरकार ने सज्जाद को भारतीय नागरिकता दे दी ...

इन मियाँ साहब सज्जाद जहीर और रजिया जहीर की चार बेटियाँ थी।

नजमा जहीर बाकर- पाकिस्तानी सज्जाद जहीर की सबसे बड़ी बेटी, जो कि नेहरू के मदरसे जेएनयू मे Biochemistry की प्रोफेसर है।

दूसरी बेटी **नसीम भाटिया** है। तीसरी बेटी है **नादिरा बब्बर** जिसने फिल्म एक्टर और कांग्रेस सांसद राज बब्बर से शादी की है , इनके दो बच्चे हैं,

आर्य बब्बर और जूही बब्बर।

सज्जाद जहीर की चौथी और सबसे छोटी बेटी का नाम है **नूर जहीर** , ये मोहतरमा भी लेखिका हैं , और जे एन यू से जुडी हैं।

नूर जहीर ने शादी नहीं की और जीवन भर अविवाहित रहने के अपने फैसले पर आज भी कायम है । चूँकि नूर जहीर ने शादी ही नहीं की तो बच्चो का तो सवाल ही पैदा नही होता ..... मगर रूकिये , यहाँ आपको निराश होना पड़ेगा। अविवाहित होने के बावजूद , नूर जहीर के चार बच्चे हैं, वो भी चार अलग-अलग पुरूषों से .....। इन्हीं नूर जहीर और ए. दासगुप्ता की दूसरी संतान है **पंखुडी जहीर।** चौंकिये मत...

ये वही पंखुडी जहीर है, जिसने कुछ ही वर्षों पहले दिल्ली में केशव कुंज के सामने खुलेआम चूमा-चाटी के लिए, किस ऑफ लव (kiss of love) के नाम से इवेंट आयोजित किया था। जी हाँ , ये वही है जो कन्हैयाकुमार वाले मामले मे सबसे ज्यादा उछल कूद मचा रही थी । इसे JNU में कन्हैयाकुमार की सबसे विश्वस्त सहयोगी माना जाता है । खुले आम सिगरेट, शराब और अनेक व्यसनों की शौकीन, इन जैसी लड़कियाँ जब महिला अधिकारों के नाम पर बवंडर मचाती हैं, तो सच मे पूछ लेने को दिल करता है,कि तुम्हारा खानदान क्या है ? और क्या है तुम्हारे संस्कार ?

बिन ब्याही माँ की, दो अलग अलग पुरूषो से उत्पन्न चार संतानों में से एक पंखुडी जहीर जैसी स्त्री, स्वयं स्त्री के नाम पे जिगत का दाग है।

यह जानकारी पाकिस्तान, इस्लामियत, कम्युनिस्टो का सड़न भरा अतीत, इनकी मानसिकता, इनका खानदान और इनके संस्कार बयां करने को काफी है। इन्हीं जैसे लोगों ने JNU की इज्जत में चार चाँद लगा रखे हैं।

पाकिस्तान मे कम्युनिस्ट पार्टी आज तक एक प्रतिशत मत वोट भी नहीं जुटा पायीं , कुल 176 वोट मिलते हैं इन्हें और पाकिस्तानी सज्जाद जहीर की औलादें, अरबन नक्सल का चोला पहनकर भारत की बर्बादी के नारे लगा रहे हैं।

JNU के कामरेडों का पाकिस्तान प्रेम और कश्मीर के मुद्दे पर नौटंकी करने का असली उद्देश्य समझ सकते हैं। ***- वर्षा सैनी***

समाचार में नक्सली विचार

जंगल के नक्सलियों का कुछ पत्रकारों के गहरे संबंध से चौथे स्तंभ की मर्यादा तार-तार हो रही है। समाचार लेने की आड़ में कुछ खबरनवीस इनकी मुखबिरी करते हैं तो कुछ इन्हें हीरो बनाते हैं तो कुछ स्वयंभू वार्ताकार बन जाते हैं। नक्सलियों से कथित अंर्तसंबंध को लेकर सेंट्रल जेल में रह रहे पत्रकार संतोष यादव से पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम और आलोक पुतुल ने। इनके द्वारा यह हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि पत्रकारों के साथ अत्याचार हो रहा है। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बस्तर में तेजी से हो रहे विकास कार्यों के कारण उखड़ रहे नक्सलियों के झूठे प्रचार किये जा रहे हैं कि सभी पत्रकारों की गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन की निगाह है, ताकि आम पत्रकार सरकार के विरूद्ध हो जाए।

दिसम्बर 2013 में ग्रमीण संवाददाता साईं रेड्डी की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इस कारण क्रूर राष्ट्रद्रोहियों ने पहले उसके घर को आग के हवाले किया फिर उसकी हत्या की। फरवरी 2013 में एक और ग्रामीण पत्रकार नेमीचंद जैन की सुकमा (छत्तीसढ़) में गोली मारकर हत्या कर दी। 2015 में पुलिस ने रायपुर से प्रकाशित हो रहे दैनिक नवभारत के संवाददाता संतोष यादव और दैनिक छत्तीसगढ़ के संवाददाता सोमारू नाग को धर दबोचा था। उधर 8 फरवरी 2016 से आईसीआरसी की पूर्व मुखिया और स्क्राल के लिए लिख रही मालिनी सुब्रमण्यम पर **हमला हुआ।** नक्सली समर्थक होता स्थानीय प्रशासन को पता लगा उनके लेख माओवादी समर्थक और देश के विरूद्ध हैं। जगदलपुर और रायपुर (छत्तीसगढ़) के कुछ धन लेकर नक्सलियों के समर्थन में रिपोर्ट तैयार कराने वाले पत्रकारों ने बस्तर की रिपोर्टिंग कर रहे अलोक पुतुल को बीबीसी हिन्दी सेवा से मुक्त इसलिए किया गया कि वह लगातार माओवादी बुद्धिजीवियों के अंतराष्ट्रीय और भारतीय संस्कृति को गलत बताने के प्रयास को महिमामंडित करता था। बस्तर से यू.एन.आई. संवाददाता और संभागीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि हमें सत्य लिखने पर हत्या की धमकी दी जाती है इसलिए नगर से बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं

राजस्थान के केन्द्रीय विश्वविधालय में अरबन नक्सल की आहट

राजस्थान के एकमात्र केन्द्रीय विश्वविधालय को पूर्व योजना के मुताबित अरबन नक्सलवाद का अड्डा बनाया जा रहा है । सामाजिक कार्य विभाग द्वारा कई बार विश्वविद्यालय में निखिल डे का व्याख्यान रखा जाता है जो मजदूर किसान शक्ति संगठन में अरुणा राय के सहयोगी हैं व अरबन नक्सल को बढ़ावा दे रहे हैं। कल्चर व मीडिया विभाग के विद्यार्थी प्रति वर्ष इनटर्नशिप करने MKSS भेजते हैं जहां तिलोनिया (बेयरफुट कालेज) मुख्यालय है।

ऐसे ही जामिया की फातिमा नजरूदिन को अग्रेजीं विभाग द्वारा आमंत्रित करना। कुलपति द्वारा कार्यक्रम में सरस्वती माँ की तस्वीर न लगाने देना व विरोध करने पर सेकुलर संस्थान है कहकर बात टाल देते हैं। एक पी जी छात्र जिसके द्वारा अरबन नक्सल टिव्टर ट्रेण्ड में सम्मिलित होने जैसी नक्सली विभिन्न गतिविधिओं में लिप्त हैं । शंकर चौधरी (आइसा, कम्यूनिष्ट छात्र सघंठन) के राष्ट्रीय टीम में है व पी.एच.डी कर रहे है। प्रो. अम्बेडकर जी व हुसैन कुनरू (कश्मीरी) लड़को को लव जिहाद में सपोर्ट करते हैं। राष्ट्रीय विचार के छात्रों को नियोजित तरीके से निष्कासित किया जाता है। अनेक ऐसे तथ्य है जो इस यूनिवर्सिटी में अरबन नक्सल की आहट देते हैं।

– यादवेन्द्र सिंह शेखावत

जुटा पाते। वरिष्ठ पत्रकार कश्यप के मुताबिक अगर पत्रकार नक्सलियों के समर्थन में लिखते हैं तो सब ठीक है, वरना कुछ भी खैरियत नहीं।

अब वे प्रकाशक मुद्रक भी बन गये। माओवादी बुद्धिजीवियों को वे सूचना प्रदान करते हैं और इस आधार पर ये सभी नक्सलियों को राष्ट्रद्रोही कार्यों को न्यायसंगत ठहराते हैं। पुलिस कार्यवाही को ये मानवाधिकार का हनन मान कर पूरे देश में संशय और भय का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। स्थानीय भाषाओं में यथा: गोण्डी, हलबी, भील, संथाली की समझ रखने वाले चुनिंदे पत्रकारों को ही है। वन में लड़ाई तो खुलेआम हो रही है, किन्तु शहरों में अति गोपनीय ढंग से की जा रही है।

– अंजनी झा